



आप प्रदर्शन करके भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की कोशिश कर... पृष्ठ-2

दिव्य भारत



विराट कोहली ने एक और उपलब्धि अपने नाम की, 300 वनडे... पृष्ठ-7

नशा तस्करों को दंडित करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही : अमित शाह

रमाकान्त पाण्डेय
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पैसे के लालच में हमारे युवाओं को नशे की अधेरी खाई में धकेलेने वाले नशा तस्करों को दंडित करने में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना है। गृह मंत्री ने कहा कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की रणनीति के साथ अचूक जांच के परिणामस्वरूप देश भर में 12 अलग-अलग मामलों में 29 नशा तस्करों को अदालतों ने दोषी ठहराया है। मादक पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसरण में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 27 जुलाई, 2019 को एनसीबी अहमदाबाद जेलन यूनिट ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन से मोहम्मद रिजवान और मो. जिशन के कब्जे से 23.859 किलोग्राम चरस जब्त की। जांच के दौरान साहिदुल रहमान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया और सभी 03 अभियुक्तों को 14 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 01 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। जुलाई 2022 में एनसीबी मंडसौर ने मध्य प्रदेश के शहडोल में ध्रुव टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर एक हैरियर और एक वैन को रोका और 123.080 किलोग्राम



गांजा जब्त किया। इस मामले में 24 फरवरी 2025 को विशेष एनडीपीएस न्यायालय, शहडोल ने चार आरोपितों शिवम सिंह, संत कुमार यादव, बालमुकुंद मिश्रा और उत्तम सिंह को दोषी ठहराया और उन्हें 12 साल के कठोर कारावास तथा 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एनसीबी चंडीगढ़ के अधिकारियों द्वारा डीएचएल एक्सप्रेस, लुधियाना में 438 ग्राम अफीम से भरी दो हॉकी स्टिक वाले पार्सल को रोका गया। पार्सल आरोपित नसीब सिंह ने बुक किया था, बुकिंग के दौरान गोबिंद सिंह उसके साथ था। अदालत ने दोनों दोषियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने (डिफॉल्ट रूप से, एक महीने की अतिरिक्त कैद) की सजा सुनाई। 30 दिसंबर 2021 को एनसीबी चंडीगढ़ जेलन यूनिट

ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भीम लामा को 390 ग्राम चरस के साथ मुंबई के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में चढ़ने से पहले रोका। 08 जनवरी 2025 को विशेष अदालत, चंडीगढ़ ने भीम लामा को 390 ग्राम चरस रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी द्वारा दिखाए गए पश्चाताप और प्रतिबंधित सामग्री की गैर-व्यावसायिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6 महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना (जुर्माना भुगतान में चुक के मामले में एक महीने का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई। 19 जून 2021 को एनसीबी कोचीन ने कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर शेरोन चिक्वाजा नामक जिम्बाब्वे की एक महिला को रोका। उसके चेक-इन सामान की जांच से 2.910 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी और जब्त हुई। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और एनसीबी कोचीन जेलन यूनिट द्वारा मामला दर्ज किया गया। 29 जनवरी 2025 को सुनाए गए विस्तृत फैसले में न्यायालय ने आरोपित को 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,00,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। 5 जनवरी 2018 को एनसीबी देहरादून ने 450 ग्राम चरस जब्त की, जिससे नमन बंसल को गिरफ्तारी हुई। मामले की जांच में 19 फरवरी 2018 को एक और सह-आरोपित, देहरादून निवासी आशुतोष उनीयाल की गिरफ्तारी हुई। एनडीपीएस कोर्ट, देहरादून (यूकेडी) ने 18 जनवरी 2025 को आरोपित नमन बंसल को 01 साल की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

दिल्ली के हर क्षेत्र में विकास को पूरा करना हमारी प्राथमिकता : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के हर क्षेत्र में विकास और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पूरी करना हमारी प्राथमिकता है। रेखा गुप्ता यहां दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिल्ली सरकार के मंत्रियों के स्वागत एवं अभिनन्दन कार्यक्रम में बोल रही थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, सांसद मनोज तिवारी और पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता और विशेष कर पूर्वांचल के कार्यकर्ता और मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अब बारी दिल्ली सरकार की है। अब भाजपा सरकार अपने किए हुए हर एक वादा को अगले पांच साल में पूरा करके दिखाएगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संगठन और भाजपा सरकार मिल कर दिल्ली को विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बनाएंगे, मुख्य काम

यमुना मड़िया की पूर्ण सफाई और वहां छोट पूजा का आयोजन करना है। उन्होंने पूरी दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा और पूर्वांचल के मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इनके बिना दिल्ली में भाजपा का सरकार बनना मुश्किल था। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सत्ता में हम 27 साल बाद भले लौटे हों परन्तु ये जीत 32 साल बाद यानि 1993 के बाद हमें मिली है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये सरकार 24 घंटे दिल्ली के विकास के लिए कार्य कर रही है। सड़क, गंदे पानी, सिवर से सम्बन्धित कोई भी समस्या अगर किसी क्षेत्र में सामने आती है तो उसके लिए 24 घंटे हम कार्य करने को तैयार हैं। जल्द ही इन समस्याओं से समाधान के लिए चार डिजिट का हेल्प लाइन नंबर जारी किया जाएगा। सभी नेताओं ने एक स्वर में दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा की मेहनत और दिल्ली में भाजपा के प्रति



पूर्वांचल के वोटों के समर्थन की सराहना की। इस मौके पर संतोष ओझा ने कहा कि दिल्ली हो या देश का कोई भी क्षेत्र, पूर्वांचल के लोग जाति से ऊपर उठ कर सिर्फ भाजपा को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने मोदी पर पूरा भरोसा है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए 225 सीट जीत कर वहां सरकार बनाएगी। कार्यक्रम में विधायक अभय वर्मा, विधायक चंदन चौधरी, प्रदेश कार्यालय मंत्री बृजेश राय, सोशल मीडिया प्रमुख डॉ. रोहित उपाध्याय मोर्चा के महामंत्री जगदम्बा सिंह, संजय तिवारी एवं विशाल चंदेल सहित प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष व लगभग 1000 कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अपनी संभावनाओं से दुनिया को आकर्षित कर रहा है भारत : उपराष्ट्रपति



नई दिल्ली, (हि.स.)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत अब वादे करने वाला देश नहीं रह गया है। भारत को अब सपनों का देश नहीं माना जाता। भारत पूरी दुनिया को अपनी संभावनाओं से आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ रविवार को केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में हलोलोकात्र, जनसांख्यिकी, विकास और भारत का भविष्य विषय पर चौथे पी. परमेश्वरन स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पी. परमेश्वरन की भारतीय मूल्यों के प्रति अटूट

प्रतिबद्धता, भारतीय लोकाचार की उनकी गहरी समझ और राष्ट्रीय एकता के लिए उनका अथक प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। सांस्कृतिक रूप से निहित और आध्यात्मिक रूप से जागृत एक आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका दृष्टिकोण पूरे देश में गहराई से गूंजता है। हाल के दशक में भारत के विकास को लेकर धनखड़ ने कहा कि जन-केन्द्रित नीतियों और पारदर्शी जवाबदेह शासन ने पारिस्थितिकी तंत्र को उछाल दिया है। 1.4 बिलियन का राष्ट्र ग्रामीण क्षेत्र में आए परिवर्तनकारी बदलाव को देखें। हर घर में शौचालय है, बिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन आने वाला है, गैस कनेक्शन है, कनेक्टिविटी, इंटरनेट और सड़क, रेल और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सहायता करने वाली नीतियां। ये हमारी विकास पथ को परिभाषित करती हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की सोमनाथ महादेव की पूजा-आरती



सोमनाथ, (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार शाम सोमनाथ महादेव की पूजा-आरती की। इससे पूर्व सोमनाथ गीतामंदिर हेलिपैड पर प्रधानमंत्री का हेलिकॉप्टर उतरा। यहां से प्रधानमंत्री मंदिर तक वाहन में गए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों का हजूम उमड़ा रहा। लोग प्रधानमंत्री के एक झलक पाने को बेताब थे। मंदिर में सोमनाथ महादेव का दर्शन के बाद विद्वान पुरोहितों ने शास्त्रोक्त विधि और मंत्रोच्चारण के साथ सोमनाथ महादेव का पूजन कराया। इससे पूर्व गीतामंदिर हेलिपैड पर कलक्टर दिग्विजयसिंह जाडेजा, एसपी मनोहरसिंह जाडेजा ने प्रधानमंत्री का स्वागत अभिवादन किया।

हिंदुओं को गैरों से ज्यादा अपनों से खतरा : हिमंत बिस्वा सरमा

कोलकाता, (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कोलकाता में आयोजित विवेकानंद सेवा सम्मान 2025 कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदुओं को अन्य धर्म या धर्मावलंबियों से अधिक अपने अंदर मौजूद तथाकथित उदारवादियों और अति वामपंथियों से नुकसान का खतरा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं मानता हूँ कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा वामपंथी और उदारवादी हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कमजोर करने की परंपरा वामपंथियों से शुरू हुई, जिसे ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता 5,000 वर्षों से भी पुरानी है और देश का इतिहास केवल 1947 में स्वतंत्रता के साथ शुरू नहीं हुआ। सरमा ने कहा, भारत स्वाभाविक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमें किसी से भी सहिष्णुता और भाईचारे का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है।



हिंदू समाज के अस्तित्व को लेकर उन्होंने कहा, हिंदू सभ्यता ने हजारों सालों में कई चुनौतियों का सामना किया है और आगे भी कायम रहेगी। हिंदू कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि देश में असली परिवर्तन उनके नेतृत्व में आया है। सरमा ने कहा, राम मंदिर 500 वर्षों बाद बन पाया है। कदाचित् भगवान श्रीराम प्रधानमंत्री की मोदी के माध्यम से ही स्थापित होना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हर तरह के सुधार हो रहे हैं। कांग्रेस शासन में हुई गलतियों को सुधारा जा रहा है। तीन तलाक खत्म हो चुका है, वक्फ

कानून पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। देश में समान नागरिक संहिता लागू होने के भी संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता की ताकत ही है कि आजादी के बाद पाकिस्तान इस्लामिक देश बना, लेकिन भारत अपने प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर कायम रहा।

हितेश मेहता का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा

मुंबई, (हि.स.)। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ रुपये के चोटाले के मुख्य आरोपित हितेश मेहता का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगी। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक चोटाले मामले की जांच कर रही पुलिस 122 करोड़ रुपये के गबन मामले के मुख्य आरोपित हितेश मेहता से पूछताछ कर रही है, लेकिन मेहता जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से पुलिस ने कोर्ट से हितेश मेहता का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मंजूरी मांगी थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। पुलिस के अनुसार न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक चोटाले में 122 करोड़ रुपये की बड़ी हेराफेरी की गई थी। इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता, बिल्डर धर्मेरा पांव और अभिमन्यु नाम का एक व्यक्ति शामिल है।

मोदी सरकार ने जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों को बढ़ावा और मान्यता दी : जितेंद्र सिंह

आलोक पाण्डेय
नई दिल्ली। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार भारत में पहली बार जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों को बढ़ावा दे रही है और उन्हें मान्यता भी दे रही है। केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहां केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) के रजत जयंती समारोह को वरुंअली संबोधित कर रहे थे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की ह्यविरासत भी और विकास भी के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसमें भारत के विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान को अत्याधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत किया गया है। इस मौके पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक डाक टिकट भी जारी किया। इसके बाद ह्यइनोवेशन फ्रंटलाइन नामक एक पत्रिका और एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की।



इस मौके पर भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि दूरदराज के गांवों में होने वाले नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों की तरह समान अवसर और संसाधन सुनिश्चित होंगे। उन्होंने भारत के ह्यनाजुक पांच से ह्यपहले पांच में तब्दील होने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके जल्द ही चौथे स्थान पर पहुंचने की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों सहित कम खोजे गए क्षेत्रों का दोहन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान उपेक्षित किया गया था। सिडबी के साथ एनआईएफ द्वारा एक अग्रणी पहल, जिसने 238 नवाचार-आधारित उद्यम परियोजनाओं को

आवश्यक जोखिम पूंजी प्रदान की है, इसे एक नई पहल बताते हुए उन्होंने इस मिथक को खारिज कर दिया कि केवल शानदार डिग्री वाले कुलीन वैज्ञानिक ही नवाचार और स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने सीएसआईआर-आईआईआईएम जम्पू द्वारा समर्थित लैब्वेडर क्रांति और सीएसआईआर-आईएचबीटी पालमपुर द्वारा संचालित फ्लोरीकल्चर क्रांति की सफलता का हवाला दिया। डॉ. सिंह ने दोहराया कि भारत की तकनीकी स्वाभाविक रूप से सस्ती और लागत प्रभावी है, जो इसे वैश्विक रूप से आकर्षक बनाती है। एनआईएफ की 25 साल की यात्रा का जश्न मनाते हुए उन्होंने घोषणा की कि भारत में 713 पेटेंट और अमेरिका में 5 पेटेंट दिए गए हैं, जो जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने में एनआईएफ की भूमिका को रेखांकित करता है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एनआईएफ भारत में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) की मेजबानी करने वाले शुरूआती संस्थानों में से एक था, जिसे अब एनआईएफ इनक्यूबेशन और उद्यमिता परिषद के रूप में जाना जाता है।

दिव्य

भारत एकेडमी

मो0 7459093657, 798608203

UPP, UPSI, SSC

रेलवे, UPSSSC

आदि प्रतियोगी परीक्षाओं

की सम्पूर्ण तैयारी।

पता- बहारिया, कुण्डा-प्रतापगढ़

'वन नेशन, वन इलेक्शन' के समर्थन में कैट का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा

नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वन नेशन, वन इलेक्शन की ऐतिहासिक पहल के समर्थन में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देश भर में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत देशभर में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के माध्यम से सेमिनार, कार्यशाला और संवाद सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चुनाव सुधारों, आर्थिक प्रभाव और समाज तथा व्यापार जगत पर सकारात्मक प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया का मानना है कि बार-बार चुनाव होने से देश की आर्थिक प्रगति बाधित होती है, सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन धीमा हो जाता है और व्यापारिक

गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो इससे व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी, साथ ही सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

अभियान के तहत व्यापारिक संगठनों के माध्यम से वन नेशन, वन इलेक्शन की जानकारी आम जनता और व्यापारियों तक पहुंचाई जाएगी। विभिन्न राज्यों में व्यापार संगठनों द्वारा विशेषज्ञों के साथ परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी। चुनाव सुधार विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, कानूनी विशेषज्ञ और नीति निर्धारकों को आमंत्रित किया जाएगा। इस अभियान के तहत देशभर के व्यापारियों से सुझाव और समर्थन जुटाए जाएंगे।

खंडेलवाल ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन से देश का लोकतांत्रिक ढांचा और मजबूत होगा, विकास कार्यों की रफ्तार तेज

होगी और व्यापार जगत को स्थिरता मिलेगी। बार-बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है और प्रशासन ठप हो जाता है। देश भर के व्यापारी कैट के झंडे तले इस ऐतिहासिक पहल का पूर्ण समर्थन करता है और इसे सफल बनाने के लिए देशभर में व्यापक जनजागरण अभियान चलाएगा।

कैट का यह अभियान व्यापारी वर्ग, सिविल सोसाइटी, नागरिक, समाज और नीति निर्धारकों को एक मंच पर लाकर वन नेशन, वन इलेक्शन की आवश्यकता पर सार्थक संवाद स्थापित करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के इस दूरदर्शी कदम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। इस अभियान से जुड़ने और समर्थन देने के लिए कैट ने देशभर के व्यापारियों और संगठनों को जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है।



नई दिल्ली में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीच शिष्टाचार भेंट।



पटना। भाकपा-माले के राष्ट्रीय सचिव दीपकर भट्टाचार्य गांधी मैदान में 'बदलो बिहार महाजुटा' रैली के दौरान भीड़ को संबोधित करते हुए।

लोकतंत्र की प्रयोगशाला हैं पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन : श्रीवास्तव

भोपाल, (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाने वाले पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन लोकतंत्र की प्रयोगशाला और परीक्षण स्थली हैं। पूरी दुनिया के साथ भारत का यह अनुभव है कि जब भी निर्वाचन संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रयोग होते हैं, तो सबसे पहले स्थानीय निर्वाचनों में होते हैं। जब महिलाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण का विचार आया, तो सबसे पहले पंचायतों और स्थानीय निकायों में इसे लागू किया गया। मध्य प्रदेश में तो निकायों में पहले 33 प्रतिशत और बाद में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसकी जितनी स्वीकार्यता पिछड़े, कहे जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, उतनी वरिष्ठ स्तरों पर अभी भी नहीं हो पाई।

राज्य निर्वाचन आयुक्त

श्रीवास्तव रविवार को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पंच राष्ट्रीय उद्यान (टाइगर रिजर्व) में आयोजित राज्य निर्वाचन आयोग की चार दिवसीय 31वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ईव्हीएम के बाद अब पेपरलेस बूथ की कल्पना को मूर्त दिया जा रहा है। पंचायत उप निर्वाचन में चुनाव पेपरलेस बूथ के माध्यम से सफलतापूर्वक कराये जा चुके हैं।

श्रीवास्तव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन लोकतंत्र की नींव हैं। यह चुनाव पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस चुनाव के माध्यम से नागरिक सीधे शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग पर चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रयोग पहली बार

एस्टोनिया में किया जा चुका है। श्रीवास्तव ने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर यह जरूरी है कि हम चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया में बदलाव करते रहें।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीवास्तव ने कहा कि चुनावी खर्च कम करने के उद्देश्य से राज्यों के बीच ईव्हीएम शेयरिंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त उनके राज्य में किए गए नवाचारों की साझा करेंगे। इससे अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकेगा। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता असम के राज्य निर्वाचन आयुक्त आलोक कुमार ने की। इस दौरान विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोग के नवाचारों को समाहित कर लिखी गई पुस्तक एक्स-चेंज@एक्स-पीरियंस इनीशिएटिव-2025 का विमोचन किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने रविवार को कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में स्थानीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया में पेपरलेस बूथ प्रणाली तथा इंटरग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाने की कार्ययोजना पर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि पेपरलेस बूथ प्रणाली में डिजिटल टूल्स अपनाने से स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया सरल होगी। सभी डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल होंगे तथा मानवीय भूल की संभावना भी कम होगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल टूल्स का उपयोग होने से चुनाव में लगने वाले अमले की संख्या में कमी आएगी तथा चुनाव खर्च भी कम होगा।

आन्ध्रप्रदेश निर्वाचन आयोग की आयुक्त नीलम साहनी द्वारा स्वचालित लोकल बांडी इलेक्शन प्रक्रिया पर प्रजेंटेशन दिया गया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनल रोल मैनेजमेंट,

पोल मैनेजमेंट के ऑटोमेशन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए अन्य आयुक्तों के साथ समस्या एवं सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की। विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों ने निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

लखनादौन एसडीएम रवि सिहाग तथा सहायक कलेक्टर पंकज वर्मा द्वारा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और सुविधाजनक निर्वाचन प्रक्रिया के लिए नवीन तकनीकों को अपनाने के संबंध में प्रजेंटेशन दिया।

साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग त्रिपुरा द्वारा राज्य में स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर संस्कृति जैन ने प्रथम सत्र के समापन पर आभार व्यक्त किया। कॉन्फ्रेंस में तीन और चार मार्च को भी विभिन्न विषयों पर विषय-विशेषज्ञ प्रजेंटेशन देंगे।

हमारा ज्ञान सनातन है, लोक कल्याण हो हमारा उद्देश्य : प्रो. नचिकेता तिवारी

भोपाल, (हि.स.)। दत्तोपंत टेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा मैपकास्ट परिसर में चल रहे त्रिदिवसीय राष्ट्रीय शोधार्थी समागम में दूसरे दिन रविवार को विविध सत्रों में देशभर से आए विद्वानों ने सम्बोधित किया। ह्यभारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक शोध विषय पर आयोजित सत्र में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर नचिकेता तिवारी ने कहा कि ज्ञान नया पुराना नहीं होता। हमारा जो ज्ञान है, वो सनातन है। वह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमें शोध में इन विधियों एवं पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सनातन के आलोक में शोध करना चाहिए, जिससे हमारा और विश्व का मंगल हो। उन्होंने कहा कि भारत एक विलक्षण सभ्यता है। यूरोपीय देश भाषा पर आधारित हैं। मध्यपूर्व धर्म पर आधारित है, जबकि हम न भाषा, न धर्म और न रंग के आधार पर जुड़े हैं, बल्कि ज्ञान के आधार पर जुड़े हैं। इसका अधिष्ठान ज्ञान है। हिन्दू महानद की धारा वैदिक है, दूसरी बौद्ध है और तीसरी धारा जैन है। चौथी धारा सिख अर्थात् गुरुओं की शिक्षा जिसका संकलन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने कहा कि लव शब्द संस्कृत के शब्द लभ्यते से आया है, जिसका अर्थ है हल्लाभ की लालसा होना। जबकि प्रेम एकात्मता की तरफ प्रेषित करता है। इसी तरह एक शब्द है 'हसबैंड' जिसका मतलब हस माने हाउस, बैंड माने बॉन्डी (जुड़ा हुआ) यानी एक ऐसा व्यक्ति जो घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो तथा घर का स्वामी हो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की प्रोफेसर

डॉ. रीता सोनी ने कहा कि भविष्य में इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रभाव हर मॉलिक्यूल पर होगा। उन्होंने योग का उदाहरण देते हुए कहा कि हम यह परंपरा सारे विश्व को बिना किसी मूल्य के दे रहे हैं। समागम में डॉ. उत्पल चक्रवर्ती ने कहा कि एआई का सबसे सटीक और सार्थक प्रयोग भाषा के क्षेत्र में हो रहा है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुवाद। उन्होंने कहा कि अनुवाद केवल भाषाओं का परिवर्तन नहीं है, बल्कि उस भाषा के मर्म को भी उसी सावधानी से दूसरी भाषा में पहुँचाना है। उन्होंने एआई से जुड़े सवालों पर कहा कि वर्तमान में एआई के जितने मॉडल्स हम देख रहे हैं, वो जनरल पर्पज मॉडल्स हैं। इसलिए उन्हें ह्वान फिट फॉर ऑल समझने से बचा जाना चाहिए। एआई के माध्यम से शिक्षा की कमियों को पूरा किया जा सकता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र में उन्होंने एआई के योगदान का जिक्र किया। दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए सांची विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. वैद्यनाथ लाभ ने कहा कि समय के साथ लोगों के चिंतन एवं अभिव्यक्ति में परिवर्तन आता है। 1192 के बाद तुर्क अफगान आए। उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला जैसी धरोहरों को नष्ट किया, मुगलों ने भी संस्कृति को कुचलने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने भारतीयों के मन में उनके प्रति जानबूझ कर नकारात्मक भावना भरने का प्रयास किया। हम इन हीन भावनाओं से तभी उबर सकते हैं, जब अपनी ज्ञान परम्परा को आत्मसात करके अपने शास्त्रों, साहित्य, दर्शन एवं वास्तविक स्रोत को जानने का प्रयास करेंगे।

1834-35 में आई मैकाले पद्धति को नकारात्मक बताते हुए उन्होंने तथ्यों पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि वेदों और शास्त्रों में कही भेद आये तो वेद को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसे ही बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है। हमारे यहाँ शैली अलग हो सकती है, लेकिन उनमें भेद नहीं होगा। शोधपत्र में नकल नहीं बल्कि मौलिकता को प्राथमिकता दें। हम यह प्रयास करें कि हमारे स्रोत तथ्यपूर्ण हों। शोध का उद्देश्य मात्र समस्या का समाधान ही नहीं, अपितु लोक कल्याण और समाजोपयोगी हो जिससे यह समाज उसका लाभ ले सके। मैपकास्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि भारत का रण और आयुध परम्परा बड़े शोध का विषय है। अच्छे शोध हेतु हमें अपने जड़ों में जाना होगा। हमें अपनी गौरवशाली परम्परा को अनुभूति करना है और उस पर काम करने की आवश्यकता है।

समाज में शोध के प्रभाव विषय पर बोलते हुए, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने भोजशाला पर किए अपने शोध के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शोध इतिहास को समझने और समाज को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि भारत की असली विरासत को पहचानने और सहेजने के लिए गहराई से शोध करने की जरूरत है। उन्होंने समाज से अनुरोध किया कि वे पारंपरिक इतिहास से आगे बढ़कर भारत के भूले-बिसरे अतीत को खोजने के लिए शोध करें।

मध्य प्रदेश के होमस्टे में ठहरना जीवन का अविस्मरणीय पल : दुर्गादास उइके

भोपाल, (हि.स.)। एमपी टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति से परिचय और प्राकृतिक सौंदर्य रू-ब-रू कराने के लिए होमस्टे ठहरने का एक लोकप्रिय और आकर्षक विकल्प बन गए हैं। इन होमस्टे के माध्यम से पर्यटक ग्रामीण जीवनशैली के साथ ही स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और खानपान अनुभव कर रहे हैं। इस अविस्मरणीय अनुभव को केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश रण अभियान परिषद मोहन नागर ने पर्यटन ग्राम बाँचा में स्वयं महसूस किया।

दरअसल, शनिवार की रात अलाव के बीच उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की और स्थानीय संस्कृति को करीब से जाना। रविवार सुबह प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भुने हरे चने के नाश्ता के साथ देशी महुआ पत्तल में कढ़ी, बेसन और प्याज के भजिये का लुत्फ उठाया। साथ ही समीप जंगल का भ्रमण भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि प्रदेश के होमस्टे में ठहरना जीवन का अविस्मरणीय पल बन गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्रामीणों से गांव के विकास को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि पर्यटन ग्राम बाँचा आकर आनंद

की अनुभूति हुई। यहां की शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण परिवेश अद्भुत है। खासकर, गांव के पारंपरिक व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे। एमपी टूरिज्म बोर्ड की यह पहल निश्चित रूप से ग्रामीण पर्यटन को नया आयाम देगी और स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड लगातार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के ग्रामपुर, साबरवानी और लाड़पुरा खास को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा चुना भी जा चुका है। फिलहाल प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत कुल 407 होमस्टे का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम होमस्टे की संख्या 171 हो चुकी है।

बेतुल जिले के घोड़ाडोंगरी विकासखंड के बाँचा गांव में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने परियोजना के अंतर्गत 2023 में इस गांव का चयन किया गया था। पिछले दो वर्षों से बैक टू विलेज (इ2व) कार्यक्रम के तहत यहां ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।



लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टीयों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती।

लॉजिस्टिक लागत में कटौती करना सरकार का लक्ष्य : प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि ई-कॉमर्स के तेजी से विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के ध्यान के कारण भंडारण और रसद क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख चालक माना जा रहा है। उन्होंने डिजिटल पहलों के एकीकरण के माध्यम से परिचालन क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही में निगम के प्रयासों की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी रविवार को यहां केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के 69वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जोशी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) जैसी सरकारी पहलों में सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिससे खाद्यान्न, दालें, कपास और मूंगफली सहित आवश्यक वस्तुओं के कुशल भंडारण, हैंडलिंग और परिवहन को सुनिश्चित किया जा सके। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

(एनएलपी) और पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ हमारा लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13-14 फीसद से घटाकर लगभग 8 फीसद के वैश्विक मानकों पर लाना है। एक अग्रणी वेयरहाउसिंग संगठन के रूप में सीडब्ल्यूसी आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास और दक्षता संवर्द्धन के माध्यम से इन उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मंत्री ने सीडब्ल्यूसी के पारंपरिक वेयरहाउसिंग इकाई से गतिशील लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता में परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी 700 से अधिक गोदामों के व्यापक नेटवर्क और 148.29 लाख मीट्रिक टन की परिचालन क्षमता के साथ दक्षता, नवाचार और विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है। वेयरहाउसिंग में भारत की ऐतिहासिक विरासत पर विचार करते हुए जोशी ने कहा कि भारत में भंडारण समाधानों का एक समृद्ध इतिहास है, जो मौ्यों और गुप्त साम्राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता और पाटलिपुत्र तक जाता है। आज आधुनिक तकनीक से प्रेरित वेयरहाउसिंग ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। भारत के वेयरहाउसिंग बाजार के उल्लेखनीय 15 फीसदी सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है,

जो 2027 तक 35 बिलियन डालर तक पहुंच जाएगा। मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास में सीडब्ल्यूसी के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया और कहा कि सीडब्ल्यूसी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 613 करोड़ के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के साथ अपनी भंडारण क्षमता को अतिरिक्त 21.65 लाख वर्ग फुट तक बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 2021 से इसकी ई-कॉमर्स क्षमता बारह गुना बढ़कर 2025 में लगभग 80 लाख वर्ग फुट हो गई है। उन्होंने परिसंपत्ति मुद्रिकरण योजना के तहत 820 करोड़ रुपये का निवेश जुटाते हुए 18 स्थानों पर सीडब्ल्यूसी की परिसंपत्तियों के मुद्रिकरण की प्रशंसा की। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत, सीडब्ल्यूसी का लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रौद्योगिकी उन्नति में निवेश और अनुकूल वातावरण बनाकर एक कुशल और पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला बनाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री वीएल वर्मा और निम्बेन जयतीभाई बंभानिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने अपने संबोधन के दौरान निबंध भंडारण आपूर्ति को सक्षम करके राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सीडब्ल्यूसी की प्रतिबद्धता को दोहराया।

सम्पादकीय

न्यायालयों में अनसुलझे मामलों की बढ़ती संख्या

देश की न्याय व्यवस्था कई महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय अदालतों में अभी भी 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से कई मामले एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख मामले दस साल से भी अधिक समय पहले शुरू किए गए थे। नीति आयोग ने सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए आगाह किया है कि मामले के समाधान की वर्तमान गति से केवल निचली अदालतों में लंबित मामलों को हल करने में 300 साल से अधिक लग सकते हैं।

भारत में, लंबित मामलों का अर्थ कानूनी ढांचे के भीतर अनसुलझे मामलों की भारी संख्या है। स्थिति विशेष रूप से निचले न्यायिक स्तरों पर गंभीर है, जहाँ अधिकांश मामले दायर किए जाते हैं और न्यायाधीशों की कमी की वजह से निबटारा नहीं हो पाता। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या भारतीय न्याय प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती है। लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है कहावत को चरितार्थ करती हैं। अदालतों में मामलों की बड़ी संख्या अदालती दक्षता में बाधा डालती है और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि करती है, जिससे त्वरित न्याय लगभग असंभव हो जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय में 82, 000 से अधिक और उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक मामले लंबित होने के कारण, निर्णयों में देरी आम बात है। मुकदमेबाजी का वित्तीय बोझ आर्थिक विकास को भी बाधित करता है, क्योंकि यह संसाधनों को खत्म करता है और व्यक्तियों और व्यवसायों को कानूनी कार्यवाही करने से हतोत्साहित करता है। भारत में न्यायिक देरी की अनुमानित लागत दो मिलियन डॉलर से अधिक है। न्याय प्रणाली पर लंबित मामलों का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। लंबे समय तक चलने वाले मामले कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को डिंगा सकते हैं। देरी का यह चक्र समस्या को और बढ़ाता है।

न्यायिक देरी में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या के लिए न्यायाधीशों का अपर्याप्त अनुपात है। भारत में, विकसित देशों की तुलना में कानूनी प्रणाली बहुत धीमी गति से काम करती है, जहाँ हर दस लाख निवासियों के लिए केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। सरकार सबसे बड़ी वादी है, जो सभी लंबित मामलों में से लगभग आधे मामलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से कई छोटे मुद्दों पर अपील में बंधे हैं। सीमित कोर्ट रूम स्पेस और पुरानी केस मैनेजमेंट प्रथाओं जैसी चुनौतियों से लंबी अदालती कार्यवाही और भी जटिल हो जाती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने 15 वर्षों में 200, 000 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की प्रभावशीलता को उजागर करता है। दुर्भाग्य से, वकील और वादी दोनों अक्सर स्थगन का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण मामले सालों या दशकों तक टल जाते हैं। मैनुअल दस्तावेजीकरण और पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भरता मामलों के समय पर समाधान में बाधा डालती है, जिससे अनावश्यक नौकरशाही बाधाएँ पैदा होती हैं।

लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कार्यवाही निरंतर हो। इसमें बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए न्यायालय स्टाफिंग और बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है। न्यायालयों की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने से प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। मामलों को अधिक तेजी से ट्रैक करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी केस प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना भी महत्वपूर्ण है। उचित रूप से प्रबंधित मामलों के समय पर समाधान तक पहुँचने की अधिक संभावना होती है। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कानूनों की निवृत्ति समीक्षा और संशोधन अनिवार्यता को कम करने और कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए आवश्यक है।

वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 स्थगन पर सख्त नियम लागू करता है। मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य करके वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने से अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। मध्यस्थता अधिनियम (2023) वाणिज्यिक और नागरिक विवादों में मध्यस्थता को अनिवार्य बनाकर इसका समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य अदालती लंबित मामलों को कम करना है। एक मजबूत लोकतंत्र न्याय के त्वरित और प्रभावी वितरण पर निर्भर करता है। न्यायिक देरी से निपटने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, मौजूदा रिक्तियों को भरना, एआई-संचालित केस प्रबंधन को अपनाना और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। न्यायिक जवाबदेही को दूरदर्शी नीति ढांचे के साथ जोड़कर, भारत की न्याय प्रणाली अधिक निष्पक्ष, सुलभ और समय पर बन सकती है।

भारतीय अदालतों में लंबित मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ-साथ प्रशासनिक, कानूनी और बुनियादी ढाँचे में सुधार शामिल हो। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

आरएनआई नं. DELHIN/2009/28518 स्वा.मि. सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक रमाकांत पाण्डेय द्वारा दिव्य भारत प्रकाशन के लिए न-93 डी नारायण नगर दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इन्फोटेक लि., प्रेस, सी-9 सेक्टर 3 नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : रमाकांत पाण्डेय, कार्यकारी सम्पादक : आलोक पाण्डेय, फोन : 7701825882, 7905152597, पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी।
E-mail : newdibhyabharat@gmail.com

महाकुंभ : वैश्विक समुदाय के लिए हैरत, भारत विरोधी ताकतों के लिए झटका

इतिहास के सबसे बड़े आयोजन, महाकुंभ की दुनिया साक्षी बनी। 45 दिनों का यह उत्सव, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। इनमें एक ही दिन में लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु थे जिनमें लाखों अनुयायियों को प्रेरित करने वाली दिव्य शक्ति ने उन्हें किसी भी अनुविधा की परवाह किए बिना आने के लिए प्रेरित किया। इतने बड़े सामाजिक के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम द्वारा की गई व्यवस्था न केवल सराहनीय है, बल्कि दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों के लिए शोध का विषय भी है। इतने बड़े आयोजन में पहली बार आए विदेशी मेहमान आयोजन की व्यापकता से हैरान थे। यह चमत्कार से कम नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन बिना कठिनाई और अविवशनीय अनुशासन के साथ सुचारू रूप से चल सका।

भले इरादा 45 करोड़ श्रद्धालुओं का था लेकिन वास्तविक गिनती 66 करोड़ से अधिक थी, जो अत्यधिक है; फिर भी, संगम पर प्रशासन शानदार था। पुरानी सनातन प्रथाओं के साथ आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस सहित आधुनिक तकनीक के संयोजन ने दुनिया को दिखाया कि केवल सनातन धर्म ही प्राचीन और नए ज्ञान दोनों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू कर सकता है। महाकुंभ 2025 को सफलता का कारण एक ही नहीं हो सकता; यह धर्म, शासन, अनुशासन और ईश्वरीय कृपा का सामंजस्यपूर्ण संयोजन था। आध्यात्मिकता से लेकर बुनियादी ढांचे, सुरक्षा से लेकर आतिथ्य तक हर पहलू को सोच-समझकर योजनाबद्ध किया गया और शानदार ढंग से अंजाम दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? एक दोषरहित, आनंदमय और आश्चर्यजनक रूप से मनोरंजक अनुभव जिसने प्रत्येक तीर्थयात्री को विस्मय में डाल दिया। सनातनियों ने यह प्रदर्शित किया है कि वे जाति, सामाजिक पद या रंग के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं करते हैं, जिसने भारत को तोड़ने वाली ताकतों को चिंतित कर दिया है क्योंकि एकजुट हिंदू उनके स्वार्थी एजेंडे और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को कुचल देंगे।

जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को महज पुजारी कहकर मजाक उड़ाया उन्होंने भी सनातन सिद्धांतों, ज्ञान और संस्कृति का पालन करते हुए एक सनातनी मुख्यमंत्री के गुणों का प्रदर्शन महाकुंभ में देखा है। मैं स्टालिन, पिनाराई विजयन और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूँ कि वे अपने राज्यों में भी ऐसा

आयोजन करके दिखायें। पश्चिमी दुनिया के लिए इतना बड़ा उत्सव आयोजित करना असंभव है। यह उन डीप स्टेट फोर्सेस के लिए स्पष्ट होना चाहिए जो भारत और सनातन धर्म को अस्थिर करने के लिए लाखों डॉलर बहा रहे हैं।

प्रेषान विपक्ष ने हर मौके पर महाकुंभ और योगी आदित्यनाथ पर हमला किया, मानो वे किसी दुर्घटना का ईतजार कर रहे थे ताकि योगी सरकार को नुकसान पहुंचाने वाली आलोचना का सहारा लिया जा सके। विपक्ष सनातनियों की भारी भीड़ से प्रेषान था, उनका मानना है कि हिंदू एकता उनके राजनीतिक करियर के लिए हानिकारक होगी, इसलिए किसी भी छोटे अवसर का उपयोग योगी आदित्यनाथ पर हमला करने और महाकुंभ की आवश्यकता के बारे में झूठी चिंताएं जताने के लिए किया जा रहा था।

कुछ आंकड़े जो इस अद्भुत आयोजन की भव्यता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं।

दो मशीनों से गंगा और यमुना से प्रतिदिन 10-15 टन कचरा निकाला जाता था। मशीन की क्षमता: 13 क्यूबिक मीटर, जो नदी के 4 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। नैनी प्लांट में कचरे का निपटारा, प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया और जैविक कचरे से खाद बनाई गई।

सेप्टिक टैंक के साथ 12,000 एफआरपी शौचालय।

सोखने के गड्ढों के साथ 16,100 प्रीफैब्रिकेटेड स्टील शौचालय।

20,000 सामुदायिक मृशालय स्थापित किए गए। कचरा संग्रह के लिए 20,000 कूड़ेदान और 37.75 लाख लाइनर बैग।

मुख्य अनुष्ठानों के बाद कचरे को साफ करने वाली विशेष स्वच्छता टीमें।

एक और घटक जिसने वैश्विक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, वह था महाकुंभ 2025 का पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण। महाकुंभ का उद्देश्य इतिहास में पहली बार हरित कुंभ बनना था, जो दुनिया भर में भविष्य के बड़े समारोहों के लिए एक मिसाल कायम करता है। व्यापक कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण पहलों ने यह सुनिश्चित किया कि गंगा हमेशा की तरह स्वच्छ बनी रहे।

जनवरी के पहले सप्ताह में इस आयोजन की आधिकारिक वेबसाइट पर 183 देशों से 33 लाख आगंतुक आए। दुनिया भर के 6,206 शहरों से

आगंतुकों ने इस साइट का उपयोग किया, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जर्मनी सबसे आगे थे। साइट के तकनीकी कर्मचारियों ने वैश्विक ट्रैफिक में वृद्धि देखी, जिसमें हर दिन लाखों उपयोगकर्ता महाकुंभ के इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के बारे में सामग्री का अध्ययन कर रहे थे। डिजिटल पहल ने सुनिश्चित किया कि आगंतुकों को जानकारी तक आसान पहुंच मिले, जिससे वे रसद की चिंता किए बिना उत्सव के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

कुंभ सहायक चैटबॉट: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यह एआई-संचालित, बहुभाषी, वॉयस-सक्षम चैटबॉट तीर्थयात्रियों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लामा एलएलएम जैसी उन्नत एआई तकनीकों द्वारा संचालित, इसने वास्तविक समय नेविगेशन और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रदान की। भाषिणी के भाषा अनुवाद ने चैटबॉट को हिंदी, अंग्रेजी और नौ अन्य भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम बनाया, जिससे समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित हुई।

महाकुंभ नगर में 66 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अच्छी तरह से सूचित हों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया सहित सभी उपलब्ध प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने का विकल्प चुना था। साइबर पेशेवर लगातार इंटरनेट खतरों की निगरानी कर रहे थे और एआई, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों का गलत फायदा उठाने वाले गिरोहों की जांच कर रहे थे। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता पहल का समर्थन करने के लिए एक मोबाइल साइबर टीम भी तैनात की गई थी।

विशेष साइबर सुरक्षा: साइबर गश्त करने के लिए 56 समर्पित साइबर योद्धा और विशेषज्ञ भेजे गए। धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, सोशल मीडिया धोखाधड़ी और फर्जी लिंक जैसे साइबर जोखिमों से निपटने के लिए महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला ग्राउंड और कमिशनरेट दोनों में 40 वैरिएबल मैनेजिंग डिस्प्ले (स्टड) लगाए गए। 1920 एक समर्पित हॉटलाइन नंबर स्थापित किया गया और प्रमाणित सरकारी वेबसाइटों को बढ़ावा दिया गया।

एआई और ड्रोन निगरानी में 2,750 एआई-संचालित कैमरे, ड्रोन, एटी-ड्रोन और वास्तविक समय

की ट्रैकिंग के लिए टेथर्ड ड्रोन शामिल थे। पानी के नीचे के ड्रोन: पहली बार, 100 मीटर की गहराई पर 24 घंटे नदी की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए थे। चेकपॉइंट्स और खुफिया दस्तों में विभिन्न पहुंच बिंदुओं पर स्क्रीनिंग, होटल और विक्रेता निरीक्षण और गश्त शामिल थे। सात-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली बाहरी परिधि से लेकर अंदर के गर्भगृह तक स्तरित सुरक्षा प्रदान करती थी। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की तैनाती और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किए गए थे। अर्धसैनिक बलों के जवानों, 14,000 होमागार्डों सहित 50,000 से अधिक सुरक्षा लोगों को तैनात किया गया इस सक्रिय रणनीति ने सभी संभावित खतरों को कम करने में मदद की और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया। अग्नि सुरक्षा प्रणाली को विशेष वाहनों और अग्निशमन स्टेशनों को शामिल करने के लिए विकसित किया गया था।

महाकुंभ 2025 में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिकित्सा व्यवस्था की गई थी। पूरे मेला क्षेत्र में 2,000 से अधिक चिकित्सा कर्मियों की तैनाती के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। बुनियादी प्रक्रियाओं से लेकर बड़ी सर्जरी तक, सभी चिकित्सा आवश्यकताओं को तेजी से पूरा किया गया।

खोया-पाया केंद्रों ने लापता लोगों को उनके रिश्तेदारों से मिलाने के लिए डिजिटल पंजीकरण और सोशल मीडिया अपडेट का इस्तेमाल किया। पूरे आयोजन के दौरान 30,000 से ज्यादा लापता लोगों को उनके परिवारों से सफलतापूर्वक मिलाया गया, जो इसकी समन्वय प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।

इस महाकुंभ ने सनातन धर्म की दिव्य और आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित किया है। असंभव को संभव में बदलने की क्षमता। सनातनियों की एकता निःसंदेह वैश्विक भलाई के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। वैश्विक मीडिया, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और दार्शनिकों को इस बात पर शोध करना चाहिए कि एक हिंदू संत क्या कर सकता है। महाकुंभ ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि कौन दिव्य ऊर्जा के साथ दुनिया का नेतृत्व कर सकता है और मानवता को ऊपर उठा सकता है।

-पंकज जगन्नाथ जायसवाल
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

यूक्रेन और नाटो देशों के साथ ट्रम्प का विश्वासघात, यूक्रेन को यूरोप का समर्थन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन के साथ जिस तरह की सौदेबाजी की जा रही है। नाटो देशों को अमेरिका ने अलग-अलग करके रखा है। उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ अमेरिका की थू-थू होना शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसकी के बीच में हाई वोल्टेज बहस देखने को मिली है। मीडिया के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने 10 लाख करोड़ की मदद यूक्रेन को दी है। वहीं नाटो देशों का कहना है, उन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद यूक्रेन को दी है। यूक्रेन के साथ पूर्व राष्ट्रपति

जो बाईडेन और नाटो देशों के बीच रूस के खिलाफ जो सहमति बनी थी। उसके अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन से भी बात नहीं करना चाहते हैं। वह एक गैंगस्टर की तरह शांति वार्ता की डील करना चाहते हैं। जबकि यह युद्ध अमेरिका और नाटो देशों के सदस्य बनने के कारण रूस के साथ हुआ है। यूरोपीय यूनियन के उपाध्यक्ष काजा क्लास का कहना है, जिस तरह से ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद फ्री वर्ल्ड को अब ट्रंप की आवश्यकता नहीं रही। यूक्रेन के पक्ष में नाटो और यूरोपीय देशों के 27 देश आए हैं। जिसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें यूरोप और अमेरिका में भविष्य में बढ़ने वाली हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाईडेन और नाटो देशों ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया था। यूक्रेन नाटो देशों का

सदस्य बनता है, तो उसे रूस के खिलाफ उसे हर संभव मदद दी जाएगी। यूक्रेन की रक्षा करने की जिम्मेदारी अमेरिका और नाटो देशों ने उठाई थी। सहायता को कर्ज नहीं माना जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद बड़ी तेजी के साथ स्थितियां बदल गई हैं। अमेरिका ने जो विश्वास यूक्रेन को दिलाया था। अमेरिका अब उससे पीछे हट रहा है। सहायता को कर्ज बताकर गुंडो की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर वसूल करना चाहता है। ट्रंप ने अपने सहयोगी नाटो देशों को भी इस मामले से अलग कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के पक्ष में एजेंट की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने जो हिस्सा यूक्रेन से युद्ध में जीत लिया है। समझौते में वह रूस को देने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं। वहीं यूक्रेन में जो माईनिंग और दूसरी खनिज संपदा

है। उस पर अमेरिका अपना अधिकार जता रहा है। यूक्रेन को इसके बाद भी इस बात की गारंटी ना तो रूस देने तैयार है, नाही अमेरिका भविष्य में यूक्रेन पर कोई हमला नहीं होगा। इसकी गारंटी देने तैयार है। शांति को बनाए रखने के लिए दोनों देश यूक्रेन की मदद करेंगे, यह गारंटी नहीं मिलने से, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसकी ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में खरी-खरी सुना दी। वार्ता बीच में छोड़कर वह लंदन पहुंच गए। लंदन में यूरोपीय देशों के नेताओं की एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है। जिसमें जर्मनी फ्रांस इटली सहित 27 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। पिछले तीन दिनों से पूरी दुनिया की राजनीतिक और सामरिक स्थितियां तेजी के साथ बदल गई हैं। यूक्रेन के समर्थन में यूरोप के सभी देश सामने आ गए हैं। नाटो देश भी यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आकर खड़े हो गए हैं। इससे

हर ओर खिले सूर्य पलाश फूल करा रहे हैं हिंदू नववर्ष के आगमन का अहसास

गांवों, जंगलों और सड़क किनारे जगह-जगह पर खिले सूर्य पलाश और सेमल के फूल इस बात का आभास करा रहे हैं कि हिंदुओं का नव वर्ष आने वाला है। रंगों का त्योहार होली के साथ ही नव वर्ष भी शुरू हो जाएगा। बसंत पंचमी के आते ही खूंदी सहित आसपास के क्षेत्रों और जंगलों में पलाश के फूल प्रकृति की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पलाश या टेसू के फूल प्रकृति के श्रृंगार हैं और इसके सूर्य रंग और आकार दीये की तरह होता है। इसकी बनावट के कारण ही अंग्रेजी साहित्यकारों ने इसे फ्लेम ऑफ फोरेस्ट या वन ज्योति की संज्ञा दी है। इन दिनों खूंदी, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम कहीं भी चले जाएं, हर ओर खिले पलाश के फूल बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि चैत्र के महीने में प्रकृति भी अपने सुंदरतम रूप में होती है। झारखंड का राजकीय पुष्प भी पलाश ही है। पलाश और सेमल के फूलों का उपयोग होली के दौरान रंग और गुलाल बनाने में किया जाता रहा है। करां रौंदे खूंदी की रहनेवाले वरिष्ठ

पत्रकार अण्ण चौधरी कहते हैं कि भले ही आज के बच्चे कमिकलयुक्त रंगों से होली खेलते हों, पर पछले लोक पलाश और सेमल के रंग और गुलाल बनाते थे। रंग बनाने के लिए फूलों को किसी बड़े बर्तन में रात भर आग में पकाया जाता है। वहीं गुलाल बनाने के लिए फूलों को धूप में सुखाया जाता है और पीसकर गुलाल तैयार किया जाता है। एक किलो फूल से लगभग आठ सौ ग्राम गुलाल तैयार हो जाता है। तोरपा के सामाजिक कार्यक्रम धर्मेन्द्र कुमार कहते हैं कि हमें हर हाल में प्रकृति के साथ चलना होगा। पलाश और सेमल के फूलों से बने रंग शरीर के लिए काफी लाभदायक हैं। इसलिए हमें रसायन युक्त रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक रंग से होली में पानी की बचत होती है। तोरपा के वैद्य नंद महतो कहते हैं कि पलाश औषधीय गुणों की खान है। इसका उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य संतोष जयसवाल कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि

वह पलाश के फूलों की खरीदारी कर उससे प्राकृतिक रंग और गुलाल का निर्माण कराए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों का प्रकृति से जुड़ाव भी होगा। झामुमो के नेता प्रदीप केशरी कहते हैं कि पूरे खूंदी जिले में भारी मात्रा में पलाश के फूल पाये जाते हैं। इसका कहीं सदुपयोग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इससे व्यावसायिक उपयोग के बारे में विचार करना चाहिए। खूंदी जिले में प्रचुर मात्रा में पलाश के पेड़ पाये जाते हैं, पर इसके उपयोग पर सरकार या प्रशासन ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। जेएसएलपीएस के एक अधिकारी बताते हैं कि पलाश के फूलों के व्यावसायिक उपयोग के बारे में जिला प्रशासन विचार कर रहा है। पलामू और हजारीबाग जिले में प्रशासन पलाश के फूलों से रंग और गुलाल बनाने के लिए पलाश के फूलों की खरीदारी करता है। प्रशासन द्वारा 25 से 30 रुपये प्रति किलो की दर से पलाश के फूलों की खरीदारी कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए रोजगार मिल जाता है।

आज का राशिफल

मेष राशि-विशेष कार्य स्थगित रखें, लेन-देन के मामले में हानि तथा चिन्ता होगी।
वृष राशि-विवादग्रस्त होने से बचें, क्लेश होगा, हानि होने की संभावना ध्यान दें।
मिथुन राशि-व्यग्रता असमंजस में रखे, विषय व्यवस्था से बचने की चेष्टा अवश्य करेंगे।
कर्क राशि-स्त्री भोग-ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा सुख-समृद्धि के साधन अवश्य बनेंगे।
सिंह राशि-समय और धन नष्ट न हो, क्लेश व अशांति, विघटनकारी तत्व परेशान करेंगे।
कन्या राशि-नवीन योजना फलप्रद होगी, भावनायें संवेदनशील बनी रहेंगी ध्यान दें।
तुला राशि-धन के व्यर्थ व्यय से बचें, कार्य कुशलता से संतोष होगा, मनोबल बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि-भाग्य का सितारा साथ देगा, समय अनुकूल नहीं कार्य स्थगित रखें।
धनु राशि-अधिकारियों का समर्थन फलप्रद होगा, व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि होगी।
मकर राशि-मान-प्रतिष्ठा बाल-बाल बचे, कार्य कुशलता से संतोष होगा।
कुंभ राशि-इष्ट मित्र सुखवर्धक होंगे तथा भाग्य का सितारा प्रबल अवश्य होगा।
मीन राशि-मनोबल उत्साहवर्धक होगा तथा कार्य कुशलता से संतोष बना रहेगा।
-अम्बुजा तिवारी

उपायुक्त डोडा ने पीएमएवाई की प्रगति की समीक्षा की, घरों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया

दिव्य भारत संवाददाता

डोडा। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ग्रामीण और शहरी दोनों आवास परियोजनाओं, लाभार्थी प्रगति और योजना के तहत वित्तीय संचितरण के मूल्यांकन पर ध्यान

नेता प्रतिपक्ष ने उपराज्यपाल से मुलाकात की

जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) श्री सुनील शर्मा ने आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की और विधानसभा के आगामी बजट सत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की, जो सोमवार, 3 मार्च, 2025 से शुरू होगा।

केन्द्रित किया गया।

बैठक में बताया गया कि पीएमएवाई-शहरी के तहत 2,093 घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1,968 घर (61.44%) पूरे हो चुके हैं। बताया गया कि डोडा शहर में 81.02%, भद्रवाह शहर में 82.47%, भद्रवाह योजना क्षेत्र में 53.66% और थाथरी शहर में 75.56% घर पूरे हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को चरणबद्ध किशोरों में कुल 282.91 करोड़ वितरित किए गए हैं, जिसमें प्लिंथ, लिटेल, छत और पूरा होने के चरण शामिल हैं।

पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत, लक्षित 30,415 घरों में से 90% पूरे हो चुके हैं, जबकि 2,935 घर निर्माणाधीन हैं। डीसी ने अधिकारियों को शेष सभी घरों को पूरा करने में तेजी लाने और 1,200 डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया,

जिन्होंने किशोरों प्राप्त कीं, लेकिन अपने घरों को पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने वसूली को सुविधाजनक बनाने और लाभार्थियों द्वारा परियोजना समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को 31 मार्च 2025 से पहले सभी लॉबित घरों को पूरा करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

डीसी ने जमीनी प्रगति की निगरानी करने और लाभार्थियों को उनके घरों को पूरा करने में सहायता करने के लिए अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र के दौरे के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी के लिए आवास मिशन के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी हितधारकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समन्वय में काम करने का आग्रह किया।



उपायुक्त डोडा ने पीएमएवाई की प्रगति की समीक्षा की, घरों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया।



नेता प्रतिपक्ष ने उपराज्यपाल से मुलाकात की।

उपायुक्त पुंछ ने रमजान के दौरान निर्बाध जलापूर्ति के लिए जल योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया

दिव्य भारत संवाददाता

पुंछ। उपायुक्त पुंछ, विकास कुंडल ने आज मध्य कामसार, मुख्य पंपिंग स्टेशन पुंछ, डुंगास सहित कई जल योजनाओं का गहन निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान, उपायुक्त ने डुंगास और मध्य कामसार दोनों पंपिंग स्टेशनों पर उच्च क्षमता वाली पंपिंग मशीनरी, विशेष रूप से 10,000 जीपीएच .150 एमएच की क्षमता वाले एचसीपी सेट की स्थापना की समीक्षा की, जिन्हें स्टैंडबाय सिस्टम के रूप में नामित किया गया है।

रमजान के आगामी पवित्र महीने के मद्देनजर, उपायुक्त ने जल शक्ति के कार्यकारी अभियंता को शेष कार्य को पूरा करने में तेजी लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, हर घर में निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

यशा मुद्गल ने पर्यटन विभाग के कैपेक्स बजट 2024-25 की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। आयुक्त सचिव पर्यटन, यशा मुद्गल ने पर्यटन विभाग के उअए बजट 2024-25 की समीक्षा के लिए नागरिक सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, इसके अलावा पर्यटन विकास प्राधिकरणों के प्रदर्शन और कामकाज का आकलन किया।

बैठक में चल रही पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन, बुनियादी ढांचे में सुधार और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में पर्यटन प्राधिकरण की परिचालन दक्षता पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

प्रशासनिक सचिव पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी), प्रबंध निदेशक जेकेटीडीसी, निदेशक पर्यटन कश्मीर, निदेशक पर्यटन जम्मू, विभिन्न पर्यटन विकास प्राधिकरणों के सीईओ और मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी), निदेशक योजना पर्यटन विभाग, सभी अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी

अभियंता पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) बैठक में शामिल हुए।

विचार-विमर्श के दौरान, आयुक्त सचिव ने चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के अलावा आवंटित धन के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सभी परियोजनाएं बिना किसी देरी के पूरी हों। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से सतत और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने, आउटरीच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में सक्रिय

हटिकोण अपनाते का आग्रह किया। टीडीए के लिए कैपेक्स बजट आवंटन की समीक्षा करते हुए आयुक्त सचिव ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए पारदर्शी वित्तीय नियोजन, धन के समय पर उपयोग और परियोजना की समय सीमा का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की पहचान करने का निर्देश दिया जो पर्यटन राजस्व और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में सक्षम हों। यशा मुद्गल ने बाधाओं को दूर करने, अनुमोदन में तेजी लाने और परियोजनाओं के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को पर्यटन संबंधी पहलों को लागू करने में जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। जम्मू और कश्मीर में समावेशी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जेकेएससीआईआरटी मंडल कार्यालय जम्मू ने डीआईटी जम्मू के सहयोग से जम्मू जिले (चरण क्व) के सेवारत शिक्षकों, मास्टर्स और व्याख्याताओं के लिए निष्ठा के तहत समावेशी शिक्षा पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया।

से 6 मार्च, 2025 तक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जम्मू में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को स्कूलों में समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान, नवीन रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं से लैस करना है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसएस), शिक्षा, शांतमनु की मुख्य अतिथि के रूप में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई।

समारोह को संबोधित करते हुए, शांतमनु ने यह सुनिश्चित करने में समावेशी शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया कि प्रत्येक बच्चे को, उनकी पृष्ठभूमि या क्षमताओं को परवाह किए बिना, समान सीखने के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि शिक्षक बहु-कार्यकर्ता हैं, जिन्हें अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है, और प्रशिक्षण उनके ज्ञान और उत्थान के लिए आवश्यक घटक हैं। इस अवसर पर, एसएस ने प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी) भी जारी किया। एससीआईआरटी जम्मू संभाग की संयुक्त निदेशक डॉ. सिंधु कपूर ने हाल ही में जेकेएससीआईआरटी संभागीय कार्यालय जम्मू द्वारा जम्मू संभाग के सभी डाइट के सहयोग से निष्ठा के तहत समावेशी शिक्षा पर अपने-अपने जिलों में श्रृंखलाबद्ध 14 प्रशिक्षणों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आईटी आयुक्त सचिव ने एलए कॉम्प्लेक्स में डिजिटल बुनियादी ढांचे की तैयारी की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, जो 3 मार्च, 2025 को शुरू होने वाला है, आयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जम्मू में विधान सभा परिसर में इंटरनेट कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे का व्यापक निरीक्षण किया।

निरीक्षण का नेतृत्व आयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, सौरभ भगत ने किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक निर्बाध और कुशल विधायी सत्र के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तैयार है।

अपने दौरे के दौरान, सौरभ भगत ने विधायी कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने में एक मजबूत आईटी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि विधानसभा हॉल, परिसर के भीतर सभी आवश्यक कमरों के साथ-

साथ मीडिया कमियों और आम जनता के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों को निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक एक्सेस पॉइंट्स (एपी) से लैस किया जाए। विधानसभा के सुचारू संचालन के लिए निर्बाध डिजिटल संचार और सूचना तक वास्तविक समय तक पहुंच सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है।

आयुक्त सचिव ने सीईओ जेकेजीए, रूपेश कुमार और एसआईओ एनआईसी जसकरण सिंह मोदी को पूरे बजट सत्र के दौरान निर्बाध कनेक्टिविटी की गारंटी देने के उपायों की देखरेख और कार्यान्वयन के निर्देश दिए। सीईओ जेकेजीए ने उल्लेख किया कि प्राथमिक 1 जीबीपीएस एनआईसी लिंक के अलावा विधानसभा हॉल में 5 जीबीपीएस का अतिरिक्त रिडंडेंट इंटरनेट लिंक प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी निर्देश

दिया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने, सेवा व्यवधानों को रोकने और इष्टतम नेटवर्क प्रदर्शन बनाए रखने के लिए सेवा विभक्तियों के साथ चार जेकेजीए संसाधन व्यक्तियों को शिफ्ट में तैनात किया जाए।

इसके अलावा, विधायकों के लिए उनकी डिजिटल दक्षता बढ़ाने के लिए शेड्यूल के अनुसार क्षमता निर्माण सत्रों की व्यवस्था की जाएगी। आईटी विभाग की यह सक्रिय पहल कुशल विधायी कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विभाग डिजिटल कनेक्टिविटी में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए समर्पित है, जो जम्मू और कश्मीर की प्रगति को और अधिक उन्नत, प्रौद्योगिकी संचालित शासन मॉडल की ओर बढ़ाता है।

भलवाल में वाटरशेड यात्रा अभियान का आयोजन

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमएसवाई 2.0) के वाटरशेड विकास घटक के तहत राष्ट्रव्यापी 'वाटरशेड यात्रा' अभियान के तहत ब्लॉक भलवाल ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी की। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना, स्थानीय भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना और प्रभावी वाटरशेड विकास रणनीतियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। जिला विकास परिषद (डीडीसी) के अध्यक्ष भारत भूषण, उत्तरी जम्मू के विधायक शाम लाल शर्मा, पूर्व पीआरआई सदस्य, सहायक आयुक्त पंचायत जम्मू, शाजादा नूर उल ऐन, ब्लॉक विकास अधिकारी भलवाल डॉ. सुनील शर्मा और आरडी एंड पीआर, आईसीडीएस, एनआरएलएम (यूएमईडी) के अधिकारियों के अलावा प्रमुख हस्तियों और ब्लॉक भलवाल के स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण स्थानीय मिट्टी और जल संरक्षण प्रथाओं में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यों का ई-उद्घाटन था। गणमान्य लोगों ने वाटरशेड प्रबंधन के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देते हुए सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मिट्टी की नमी में सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वाटरशेड विकास आवश्यक है। यह वैन जम्मू और कश्मीर में लगभग 2,400 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है, जिसमें इंटरैक्टिव कार्यशालाओं, सामुदायिक गतिविधियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से 500,000 से अधिक निवासियों को लक्षित किया गया है। अभियान का समापन आज जम्मू में हुआ, जिसमें वाटरशेड संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन और वर्षा जल संचयन में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।



अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा ने समावेशी शिक्षा पर जेकेएससीआईआरटी के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत अभियान (जी) के तहत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कमियों को दूर करने पर जोर दिया

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी कार्यान्वयन योजना और आने वाले वर्ष के लिए तैयारी की गई योजना के तहत की गई प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अलावा सूचना एवं सामान्य प्रशासन के आयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, ग्रामीण स्वच्छता महानिदेशक, सहिता महानिदेशक और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

डुल्लू ने विभाग को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रत्येक पंचायत में किए गए कार्यों का पूर्ण निरीक्षण करने पर जोर दिया, ताकि इस मिशन के तहत निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कमियों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों को मूल रूप से स्वच्छ और स्वच्छ दिखना

चाहिए, क्योंकि मिशन के तहत जमीनी स्तर पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कचरे के प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने एसबीएम (जी) के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की नियमित निगरानी के लिए पोर्टल को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी परिसंपत्तियों की परिकल्पना हमारे गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए की गई है और इनमें से प्रत्येक सामुदायिक परिसंपत्ति का उपयोग उन निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिनके लिए इन्हें बनाया गया है। मुख्य सचिव ने विभाग को इन परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के लिए भी एक उचित तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने इन गांवों और पंचायतों में स्वतंत्र निकायों के माध्यम से इन परिसंपत्तियों के वास्तविक उपयोग के लिए उचित रूप से उपयोग को प्रमाणित करने के लिए कहा। जल शक्ति विभाग के एसएस शालीन काबरा ने भी इस मिशन के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अपनी अंतर्दृष्टि से अवगत कराया।

उन्होंने विभाग को देश भर में इस मिशन को वित्तपोषित करने वाले केंद्र सरकार के विभाग द्वारा किए गए अवलोकनों का विश्लेषण करने की सलाह दी। काबरा ने अन्य विभागों द्वारा अपनाए गए कुछ समानांतर मॉडलों का अध्ययन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, खासकर जल जीवन मिशन के तहत बड़ी संख्या में सार्वजनिक परिसंपत्तियां बनाई गई हैं। उन्होंने इन स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए विभाग द्वारा वसूली गए शुल्क और बाद में खर्च किए गए शुल्कों का उचित लेखा-जोखा रखने का भी सुझाव दिया।

सचिव, आरडीडी, ऐजाज असद ने बैठक में एसबीएम (जी) के तहत विभाग द्वारा अब तक दर्ज की गई संचयी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) 2025-26 के तहत प्रत्याशित परिणामों को भी सामने रखा, जिसके लिए केंद्र सरकार के समक्ष 364.50 करोड़ रुपये (10% यूटी शेयर को छोड़कर) की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

अमेरिकी डॉलर में मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से बाजार में बढ़ी बिकवाली

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार खतरे के निशान के दौर से गुजर रहा है। इसकी एक वजह है विदेशी निवेशकों (फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स) का मोहभंग। ने फरवरी में भारतीय शेयर बाजारों से 34,574 करोड़ रुपए निकाले हैं। वहीं 2025 के पहले दो महीनों जनवरी और फरवरी में फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने टोटल 1.12 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है। जनवरी में फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 78,027 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे।

विशेषज्ञों के मुताबिक, भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार पैसों निकाल रहे हैं। दिसंबर 2024 में फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजारों में 15,446 करोड़ रुपए निवेश किए थे।

वहीं पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेलस बने रहे। वहीं डॉमेस्टिक

इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बायर्स बने रहे। प्रोविजनल डेटा के अनुसार, 28 फरवरी को फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 11,639.02 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि डॉमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 12,308.63 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। ट्रेडिंग सेशन के दौरान, डॉमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 28,065.55 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 15,756.92 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। वहीं फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 39,239.44 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 50,878.46 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे।

बाजार की हालिया बिकवाली की मुख्य वजह अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं हैं। इससे निवेशकों का ध्यान अमेरिकी एसेट्स की ओर बढ़ रहा है। वित्त-वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनियों के नतीजे कमजोर रहे हैं, जो अनिश्चितता के माहौल को दशाता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के

अनुसार, भारत में हाई वैल्यूएशन की वजह से फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिकवाली कर रहे हैं। वे अपना पैसा चीन के शेयरों में लगा रहे हैं, जहां वैल्यूएशन कम है। इतना ही नहीं फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़े पैमाने पर बिकवाली कर रहे हैं, जबकि यह सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसकी वैल्यूएशन आकर्षक है।

इसके अलावा फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेट या बॉन्ड बाजार से भी पैसा निकाल रहे हैं। फरवरी महीने में फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड बाजार से जनरल लिमिटेड के तहत 8,932 करोड़ रुपए और वॉलंटरी रिटेंशन रूट से 2,666 करोड़ रुपए निकाले। फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 2024 में भारतीय बाजार में निवेश 427 करोड़ रुपए रहा था। इससे पहले 2023 में फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.71 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। वहीं 2022 में फरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार से 1.21 लाख करोड़ रुपए की निकासी की थी।



सर्बिया में नोवी सैड रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर छात्र और विरोधी दलों के समर्थक अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर 15 मिनट का मौन रखते हुए।



यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमले में घायल हुए एक व्यक्ति को निकालते हुए राहतकर्मी और चिकित्सक।

ओली के अमेरिका दौरे में काला झण्डा दिखाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर डिपोर्ट करने की तैयारी

काठमांडू, (हि.स.)। पिछले वर्ष सितंबर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अमेरिका दौरे में उन्हें काला झण्डा दिखाने, विरोध प्रदर्शन करने और उनके कार्यक्रम को नहीं होने देने के आरोप में अमेरिकी सुरक्षाकर्मियों ने एक नेपाली व्यक्ति को गिरफ्तार कर नेपाल डिपोर्ट करने की तैयारी की गई है।

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नेपाली राज दूतावास द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर व्यक्ति मोहन जंग थापा को शनिवार रात को पेंसिल्वेनिया एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने नेपाली दूतावास को इस बात की जानकारी देते हुए गिरफ्तार किए गए थापा को नेपाल डिपोर्ट करने की भी जानकारी दी है। रवि

लामिछाने के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अमेरिकी चैंप्टर के प्रमुख रहे मोहन जंग थापा पर सितंबर के दूसरे हफ्ते में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सहभागी होने गए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को काला झण्डा दिखाने और जहां वे ठहरे हुए थे, उस होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया है। रवि लामिछाने की गिरफ्तारी के विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री ओली द्वारा नेपाली डायसपोरा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा था। उस समय अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने नेपाली राजदूतावास को इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली के व्यापक विरोध की बात कहते हुए कार्यक्रम रद्द करने का सुझाव

दिया था जिसके बाद नेपाली दूतावास ने ओली के इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। उसी समय नेपाल की तरफ से मोहन जंग थापा के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। दूतावास के इस शिकायत के पांच महीने बाद अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने थापा को गिरफ्तार किया है।

वाशिंगटन डीसी में नेपाली दूतावास द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मोहन जंग थापा को इस समय फिलाडेल्फिया स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दूतावास ने बयान जारी कर कहा है कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा कर आरोपी थापा को जल्द ही नेपाल के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

जापान ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ा सबसे कम बच्चे इस साल पैदा हुए

टोक्यो। जापान की जन्म दर पिछले 9 साल से लगातार कम होती जा रही है। जिसका असर जापान की अर्थव्यवस्था और जापान की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थितियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। 2024 में जापान में केवल 7,20,985 बच्चों का जन्म हुआ है। 2023 की तुलना में यह पांच फीसदी कम है। 125 साल पहले की जन्म दर से भी कम है। जापान में मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। 2024 में जापान के 16 लाख लोगों की मौत हुई है। जापान की आबादी में 9 लाख की कमी आ गई है। जापान की घटती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर जापान के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। जापान की 30 फीसदी आबादी 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की है। जन्म दर को यदि नहीं बढ़ाया गया, तो जापान का

अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। कोविड महामारी के बाद विवाह की दर कम हो गई थी। 2024 में 2.02 फीसदी की वृद्धि हुई है। सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के लिए आवास सब्सिडी देना शुरू की है। सरकार ने डेटिंग ऐप भी लॉन्च किया है। जापान की सरकार द्वारा बच्चा पैदा करने के लिए दंपतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दक्षिण कोरिया में भी जनसंख्या तेजी के साथ घट रही है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र नहीं होने के कारण 49 स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं।

स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी कम हो गई है। दक्षिण कोरिया में जो स्कूल बंद किया जा रहे हैं। उनमें 38 प्राथमिक स्कूल 8 मिडिल स्कूल और 3 हाई स्कूल शामिल हैं। इसके पहले 2023 में 22 स्कूल बंद हुए थे। 2024 में 33 स्कूल बंद हुए थे।

अरबों डॉलर देने के बाद भी यूक्रेन दिखा रहा अमेरिका को आंख, भड़के ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से यूक्रेन की दिल की धड़कन और तेज हो गई है। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी टैक्सपेयर का पैसा यूक्रेन के युद्ध में बर्बाद करे, क्योंकि जितना पैसा अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है उतना कई देशों को जीडीपी भी नहीं है। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी यूक्रेन जीत नहीं सका है। यही कारण है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है।

शुक्रवार को यह तनाव दुनिया के सामने आ गया, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हो गई। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन पर 300-350 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जबकि यूरोप ने सिर्फ 100 बिलियन डॉलर दिए हैं। ट्रंप के दावे कई बार गलत साबित होते रहे हैं।

मौजूदा आंकड़े दिखाते हैं कि ट्रंप का बयान में सचचाई नजर नहीं आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक कुल 119.7 बिलियन डॉलर की सहायता यूक्रेन को दी। अमेरिकी रक्षा विभाग का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है, जिसमें यूरोप में सैन्य प्रशिक्षण और अमेरिकी रक्षा स्टॉक्स की भरपाई भी शामिल है, जिसका कुल खर्च 182.8 बिलियन डॉलर बताया है, लेकिन दोनों ही आंकड़े ट्रंप के दावे से कम हैं। अब तक ट्रंप के 350 बिलियन डॉलर के दावे को लेकर कोई सफाई नहीं दी है।

ट्रंप का यह कहना कि अमेरिका ने 300 बिलियन डॉलर और यूरोप ने 100 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं इसमें काफी बड़ा अंतर दिखता है। नाटो प्रमुख के मुताबिक 2024 में नाटो सहयोगियों ने यूक्रेन को 51.89

बिलियन डॉलर की सुरक्षा मदद दी थी, जिसमें से करीब 60 फीसदी यूरोप और कनाडा से आया। अमेरिका कई मामलों में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा दानदाता है, लेकिन यूरोप ने संयुक्त रूप से इससे ज्यादा खर्च किया है। 2022 और 2024 के अंत के बीच पूरे यूरोप ने यूक्रेन पर 138.7 बिलियन डॉलर खर्च किए।

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों जब अमेरिका गए थे तब ट्रंप ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि यूएस को उसका पैसा नहीं मिलेगा जबकि यूक्रेन को मिलेगा। जिस पर मैक्रों ने असहमति जताई और कहा कि यूरोप और अमेरिका दोनों ने अनुदान और ऋण दिया था। अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा अनुदान यूक्रेन को दिया है, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने कर्ज ज्यादा दिया है।

पाकिस्तान के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन भेजेगा चीन

बीजिंग। चीन अंतरिक्ष में वर्चस्व जमाने के लिए काम कर रहा है। उसने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है, जिसका नाम तियांगोंग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी सहयोग बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन पर भेजने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन पर भेजकर, चीन उसे भारत के मुकाबले खड़ा करना चाहता है। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) जाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आईएसएस से बाहर निकलकर अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईएसएस के साथ मिलकर चीन स्पेस में अपने सैन्य कार्यक्रम को नहीं बढ़ा सकता था। चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन नवंबर 2022 में तैयार हो गया था। चीन की कोशिश है कि इसमें नया मॉड्यूल जोड़कर इसका विस्तार किया जाए। स्पेस स्टेशन बनाकर चीन अंतरिक्ष की दुनिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाले आईएसएस को साल 2030 में बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद एलन मस्क अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। वहीं भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए काम कर रहा है, जिसका निर्माण अगले 10 सालों में होने की संभावना है। चीन की कोशिश अंतरिक्ष में वर्चस्व हासिल कर अपने सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाना है और इसीलिए उसने पाकिस्तान के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन पर भेजने का फैसला किया है।

रूस को मिलेगा फ्री हैंड, ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी एजेंसियां हुई सक्रिय

वाशिंगटन/कीव। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की बहस रोलबल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव ला सकती है। यूक्रेन में जेलेंस्की की कुर्सी पर खतरा पैदा हो गया है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से बदला लेने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एजेंसी जेलेंस्की सरकार का तख्तापलट करने के अभियान में सक्रिय हो गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस के साथ जर्मन में मदद मांगने के लिए अमेरिका आए थे। यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में बात कुछ ऐसी पलटी कि जेलेंस्की को न सिर्फ खाली

हाथ लौटना पड़ा, बल्कि अमेरिका से रिश्ते भी बिगड़ गए। जानकारों का कहना है कि ट्रंप ने अपने सारे कार्ड खेल दिए हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बहस के बाद जेलेंस्की का मनोबल बुरी तरह कमजोर हो चुका है। यह भी मुमकिन है कि रूस यूक्रेन में तख्तापलट करवा सकते हैं। रूस पर भी आरोप लगे हैं कि उसने यूक्रेन में कठपुतली सरकार बनवाई थी। अगर रूस एक बार फिर ऐसी कोशिश करता है तो संभावना है कि अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी सीआईए भी इसमें मदद कर सकती है।

अमेरिका पहले भी अपने फायदे के लिए दुनिया में कई बार तख्तापलट करवा चुका है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को बाहर करने

के लिए अमेरिका ने तालिबान को बनाया। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाद में अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ ही 20 साल लड़ाई लड़ी। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट में अमेरिकी का हाथ होने का आरोप लगा था। राष्ट्रपति पुतिन ने आरोप लगाया था कि 2014 में अमेरिका की वजह से यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थक माना जाता था। 2014 में तख्तापलट के कारण उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा था। ट्रंप दबाव बनाने के लिए रूस के साथ शांति वार्ता से यूक्रेन को पूरी तरह बाहर कर सकते हैं।



लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर जैलेंस्की।

जेलेंस्की के सूट के बाद अब रामास्वामी के नंगे पैर होने पर भड़के अमेरिकन

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इसलिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा था क्योंकि वह सूट पहनकर ट्रंप से नहीं मिले थे। ट्रंप के साथ पत्रकारों का सामना करते समय तो एक अमेरिकी पत्रकार ने जेलेंस्की से सूट पहनने को लेकर सवाल भी पूछ लिया था। अब ट्रंप के सहयोगी भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को लेकर विवाद शुरू किया गया है। रामास्वामी पर एंटी अमेरिकन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा है।

विवेक रामास्वामी का एक साक्षात्कार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपने घर पर नंगे पैर दिखाया गया है। इसके लिए भारतीय अमेरिकी उद्यमी रामास्वामी की आलोचना हो रही है। रामास्वामी के अपने घर में नंगे पैर बैठने को असभ्य और एंटी अमेरिकन कहा जा रहा है। जिस साक्षात्कार के लिए उन्हें निशाने बनाया गया है, वह पिछले साल का है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही फोटो के साथ एक यूजर ने लिखा कि विवेक कभी भी ओहायो के गवर्नर नहीं बनेंगे। यह अमेरिका के लिए अस्वीकार्य है।

एक अन्य यूजर ने कहा कि विवेक को कम से कम मोजे तो पहनने की चाहिए थे। उसने लिखा- शायद जब आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में किसी पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हों, तो कम से कम मोजे तो पहने ही होंगे। है ना एक अन्य यूजर लिखा कि नंगे पांव रहकर हमें शिक्षा पर व्याख्यान देना कितना असभ्य था। हर कोई उनकी आलोचना ही नहीं कर रहा है। कुछ यूजर्स विवेक के बचाव में भी आए हैं। एक ने विवेक की नंगे पैर होने पर आलोचना को सबसे मूर्खतापूर्ण तर्क करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नंगे पैर अपने घर में जाना एंटी-अमेरिकन नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग सिटकॉम देखते हुए बड़े हुए हैं, जहां वे बिस्तर पर अपने जूते पहनते हैं। कुछ दूसरे यूजर्स ने बताया कि घरों के अंदर जूते उतारना एक सांस्कृतिक है, जिसमें दक्षिण और पूर्वी एशिया भी शामिल है।

एक अन्य यूजर ने लिखा, करीब सभी भारतीय अपने घरों में नंगे पैर चलते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक दूसरे यूजर्स ने कहा कि भारतीय परंपरा में किसी के घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने की प्रथा है। इसे सम्मान और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है,

क्योंकि यह बाहर से गंदगी और कीटाणुओं को घर में आने से रोकता है। इस प्रथा का व्यापक रूप से पालन किया जाता है।

गाजा में मानवीय मदद की एंट्री पर रोक

गाजा। इजराइल ने रविवार को गाजा में जानी वाली मदद पर एंट्री बैन कर दी है। शनिवार को इजराइल और गाजा के बीच पहले फेज का सीजफायर खत्म हो गया। अगले फेज के लिए कोई सहमति न बनने के चलते इजराइल इससे पीछे हट गया है।

इजराइली पीएम के ऑफिस ने इस फैसले को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है लेकिन ये चेतावनी दी है कि अगर हमारा सीजफायर जारी रखने के अमेरिकी प्रस्ताव को नहीं मानेगा तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल, इजराइल ने अमेरिका समर्थित एक प्रस्ताव को अपनाने की बात कही थी, जिसके तहत रमजान और पासओवर के दौरान सीजफायर जारी रखने की योजना थी। इसके बदले, गाजा में बचे हुए आधे बंधकों को रिहा करने की शर्त रखी गई थी।

विदर्भ ने तीसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब, केरल का टूटा सपना

नागपुर, (हि.स.)। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-2025 का खिताब जीत लिया है। विदर्भ और केरल के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला ड्रा रहा। ऐसे में पहली पारी की बढ़त के आधार पर विदर्भ की टीम चैंपियन बनी।

मैच में विदर्भ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 379 रन बनाए थे। इसके जवाब में केरल की पहली पारी 342 रन पर समाप्त हुई। इससे विदर्भ को पहली पारी के आधार पर 37 रन की बढ़त मिली। फिर दूसरी पारी में विदर्भ की टीम ने मैच के पांचवे दिन एवं अंतिम दिन तक 9 विकेट के

नुकसान पर 375 रन बनाए। इसके बाद दोनों टीमों ने ड्रा पर सहमति जताई।

विदर्भ ने तीसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब विदर्भ की टीम ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इससे पहले टीम 2017-18 और 2018-19 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी थी। वहीं टीम 2023-24 में उपविजेता रही थी। केरल की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसके चैंपियन बनने का सपना टूट गया।

विदर्भ की पहली पारीविदर्भ की टीम ने पहली पारी में 123.1 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 379 रन बनाए थे। टीम के लिए पहली पारी में सबसे ज्यादा रन

दानिश मालेवार ने बनाए। उन्होंने 285 गेंद खेलते हुए 15 चौके और तीन छक्कों की मदद से 153 रन की बेहतरीन पारी खेली।

करुण नायर ने 188 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली। इनके अलावा नचिकेत भूते 32 रन, यश ठाकुर 25 रन, कप्तान अक्षय वाडकर 23 रन और ध्रुव शोरे ने 16 रन का योगदान दिया। केरल की ओर से एमडी निधीश और ईडन एप्पल ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। एन बेसिल ने दो और जलज सक्सेना ने एक विकेट लिया।

केरल की पहली पारीकेरल की टीम ने अपनी पहली पारी में 125 ओवर बल्लेबाजी करते

हुए 342 रन बनाए। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान सचिन बेबी ने बनाए। उन्होंने 235 गेंदों का सामना करते हुए 98 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए। कप्तान के अलावा आदित्य सरवटे ने 185 गेंदों में 79 रन की उपयोगी पारी खेली। अहमद इमरान ने 37 रन, मोहम्मद अजहरुद्दीन 34, जलज सक्सेना 28 रन का योगदान दिया। विदर्भ की ओर से दर्शन नालकंडे, हर्ष दुबे और पार्थ रेखाडे ने क्रमशः 3-3 विकेट अपने नाम किए। यश ठाकुर ने एक विकेट हासिल किया।

विदर्भ की दूसरी पारी और मैच ड्रादूसरी पारी में विदर्भ की टीम ने मैच के पांचवे दिन एवं

अंतिम दिन तक 9 विकेट के नुकसान पर 375 रन बनाए। इसके बाद मैच ड्रा घोषित कर दिया गया। दूसरी पारी में करुण नायर ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 295 गेंदों में 135 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और दो छक्के लगाए। दानिश मालेवार 73 रन और दर्शन नालकांडे ने नाबाद 51 रन की पारी खेली। अक्षय कणेवार 30, कप्तान अक्षय वाडकर 25, यश राठौड़ ने 24 रन बनाए। केरल की ओर से आदित्य सरवटे ने 4 विकेट झटके। अक्षय चंद्रन, एमडी निधीश, ईडन एप्पल, बेसिल और जलज सक्सेना ने क्रमशः 1-1 विकेट हासिल किया।



काहिरा में महिलाओं के पैटार्थलन विश्वकप फाइनल बाधादौड़ में इटली की एरोरा टोएनेटी भाग लेती हुई।



चीन में एफसी एशियन कप फुटबॉल में जीत के बाद ट्रॉफी उठाये हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम।

विराट कोहली ने एक और उपलब्धि अपने नाम की, 300 वनडे मैच खेलने वाले सातवें भारतीय खिलाड़ी बने

दुबई, (हि.स.)। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में उतरते ही वनडे में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। कोहली का यह वनडे करियर का 300वां मुकाबला है। इस तरह वह भारत के लिए 300 वनडे मुकाबले खेलने वाले सातवें खिलाड़ी बन गए हैं।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम रविवार को अपना आखिरी ग्रुप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है। यह मैच पूर्व कप्तान एवं स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए काफी खास है।

यह मैच कोहली के करियर का 300वां वनडे मुकाबला है। वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने करियर में इतने या इससे ज्यादा वनडे मैच खेले हैं।

सातवें भारतीय खिलाड़ी बने कोहली-विराट कोहली 300 वनडे मुकाबले खेलने वाले सातवें

खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले भारत के छह खिलाड़ियों ने 300 या इससे ज्यादा वनडे मैच खेले हैं। इनमें शीर्ष पर पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने 463 वनडे मैच खेले हैं। दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने 347 वनडे मैच खेले हैं। राहुल द्रविड़ ने 340, मोहम्मद अजहरुद्दीन 334, सौरव गांगुली 308 और युवराज सिंह ने 301 वनडे मैच खेले हैं। अब इस खास सूची में कोहली का नाम भी जुड़ गया है।

बीसीसीआई ने दी बधाई-कोहली को 300वां वनडे मैच खेलने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बधाई दी है। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि विराट कोहली को उनके 300वें वनडे मैच के लिए बधाई।

2008 में श्रीलंका के खिलाफ किया था पदार्पण-विराट कोहली ने वर्ष 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में पदार्पण किया था। तब से इस प्रारूप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। इस मैच से पहले कोहली ने 299 वनडे मुकाबले में 58.20 की औसत से 14 हजार 85 रन बनाए हैं। वनडे में कोहली के नाम 51 शतक और 73 अर्धशतक दर्ज हैं।

दिल्ली

सोमवार को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सीएजी की रिपोर्ट पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा सत्र में सोमवार को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा सीएजी की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के बाद उस पर चर्चा शुरू की गई थी।

इसमें भाजपा विधायकों ने सीएजी रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि आआपा सरकार की स्वास्थ्य क्रांति केवल विज्ञापनों तक ही रही। उनकी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं विज्ञापनों में शुरू होकर खत्म भी हो गई। आआपा सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट बढ़ाकर

बंद बांट की है। उन्होंने दिल्ली की जनता के पैसे को लूटने का काम किया है। आज भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डाक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और दवाइयों की भारी कमी है। कोरोना काल में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए गए पैसा का उपयोग भी आआपा सरकार नहीं कर पाई।

उधर, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने के बाद सभी विभाग सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह हिरसा ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को

ईंधन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में बड़े होटलों, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली एयरपोर्ट, बड़े निर्माण स्थल पर तुरंत एंटी-स्मॉग गन लगवाना अनिवार्य करने जा रही है। इसी तरह हम सभी व्यापारिक कॉम्प्लेक्स के लिए भी यह अनिवार्य करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार गंभीर है। इसके साथ-साथ दिल्ली में अब किसी भी व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं वाले सर्कुलर से साफ है कि भाजपा सरकार दिल्लीवालों को राहत देने में जुटी हुई है।

हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान जहांगीर पुरी निवासी मलकीत सिंह (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद किया है।

जांच में पता चला है कि आरोपित पहले से डकैती, हत्या के प्रयास सहित छह मामलों में शामिल रहा है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी सतीश कुमार ने रविवार को बताया कि क्राइम ब्रांच जघन्य अपराधों में शामिल फरार आरोपितों का पता लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है।

इसी क्रम में प्रशांत विहार की

क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि मलकीत सिंह डकैती व हत्या के प्रयास के मामलों में वांछित है और वह किसी से मिलने के लिए रोहिणी इलाके में आने वाला है। सूचना को पुछा कर पुलिस टीम ने रोहिणी सेक्टर-10 के पास जाल बिछाया और आरोपित के आते ही उसे दबोच लिया।

डीसीपी के अनुसार पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद किया।

पूछताछ के दौरान मलकीत सिंह ने खुलासा किया कि नशे के चक्कर में वह बुरी संगत में पड़ गया। नशे की लत को पूरा करने के लिए वह झपटमारी और डकैती करने लगा।

ठगी के मामले में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जाली दस्तावेजों के जरिए गुरुग्राम की एक संपत्ति का मालिक बताकर बेचने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने संपत्ति बेचकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से 5.78 करोड़ रुपये की ठगी की।

मूल मालिक के अदालत में शिकायत करने पर ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद पीड़ित ने आर्थिक अपराध शाखा में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोहम्मद सलमान और रानी कपूर (बदला हुआ नाम) के रूप में हुई है।

आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी विक्रम के पोरवाल ने रविवार को बताया कि दिसंबर

2024 को कंस्ट्रक्शन कारोबारी अजय कुमार अग्रवाल से शाखा में ठगी की शिकायत दी। जिसमें उन्होंने मोहम्मद सलमान पर गुरुग्राम स्थित एक प्लॉट की बिक्री कर उनसे 5.78 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया।

वह सलमान को पहले से जानते थे। उन्होंने बताया कि वह पहाड़गंज में उनके कार्यालय से संपर्क किया। आरोपित ने बताया कि संपत्ति शास्त्री नगर निवासी रानी कपूर (बदला हुआ नाम) की है। जिसका माप 1,340 वर्ग गज है।

मोहम्मद सलमान ने उन्हें संपत्ति के मूल दस्तावेज दिखाए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इन दस्तावेजों के आधार पर आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस

लिमिटेड से पांच करोड़ का ऋण लिया। फिर शिकायतकर्ता ने संपत्ति का दौरा किया। जहां एक बोर्ड देखकर वह चौंक गया। जिसमें बताया गया था कि संपत्ति कविता शर्मा (बदला हुआ नाम) की है।

पीड़ित के पुछने पर सलमान ने कहा कि बोर्ड उन्होंने लगाए हैं। कुछ दिन बाद शिकायतकर्ता को गुरुग्राम कोर्ट से एक नोटिस मिला, जिसमें मूल मालिक कविता शर्मा ने रानी कपूर द्वारा उनके नाम पर निष्पादित बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग की गई थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने शाखा में शिकायत दर्ज कराई। इधर पुलिस ने मामले दर्ज करने के बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर आरोपितों को गिरफ्तार किया।

मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। उत्तरी जिले की स्पेशल स्टाफ ने दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानकर उसकी बाइक लूट ली थी। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सहारनपुर उप निवासी इतेजार कुरेशी (46) और दिल्ली के बुद्ध विहार निवासी कृष्णा झा उर्फ किशन (31) के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो देशी कट्टे, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। जांच में बाइक मोती नगर इलाके से चोरी की निकली।

पुलिस के अनुसार कृष्णा झा पहले से हत्या के प्रयास, डकैती समेत 12 मामलों में शामिल रहा है जबकि इतेजार के ऊपर तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है।

उत्तरी जिले के डीसीपी राजा बाठिया ने रविवार को बताया कि 26 फरवरी को उत्तरी जिला पुलिस की जगुआर टीम कश्मीरी गेट से बुराड़ी प्लाईओवर तक पेट्रोलिंग पर निकली

थी। उसी दौरान वजीराबाद प्लाईओवर के पास उन्हें कुछ सदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने पीछा करना शुरू किया और भलस्वा सर्विस लेन के पास उन तीनों बदमाशों को रोक लिया। इनमें से एक बदमाश मीके से फरार हो गया। अन्य दो बदमाशों ने जब खुद को पुलिसकर्मीयों से घिरा हुआ देखा तो कास्टेबल दिनेश पर पिस्तौल तानकर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए।

डीसीपी के अनुसार शनिवार रात जिले की स्पेशल स्टाफ को जानकारी मिली कि जिन बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानी थी, वे मुखर्जी नगर के आईटीआई के पास तारा चौक के पास आने वाले हैं। सूचना को पुछा कर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया और बदमाशों को आता देख रुकने का इशारा किया लेकिन बदमाशों भागने लगे और पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें पुलिस ने धर दबोचा।

पुलिस से बचने की कोशिश में मेट्रो पिलर से टकराई शराब तस्कर की कार, गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। द्वारका जिला पुलिस से बचकर भाग रहे शराब तस्कर की होंडा सिटी कार मेट्रो पिलर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। नंगली मेट्रो स्टेशन के समीप हुई इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने शराब तस्कर को धर दबोचा। आरोपित की पहचान सन्नी के रूप में हुई है। उसके कब्जे से होंडा सिटी कार तथा 68 पेटी शराब बरामद की गई है। आरोपित के खिलाफ पहले से चार मामले दर्ज हैं।

द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली कि हरियाणा से एक युवक शराब की तस्करी में लिप्त है। जो द्वारका और साउथ जिले में शराब की सप्लाई करता है। इस आधार पर गुरुग्राम सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस टीम ने नजफगढ़ इलाके के नंगली मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार रात घेराबंदी की। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाकर कार बैक कर भागने की कोशिश की। इस दौरान फुटपाथ पर बने मेट्रो पिलर से कार टकराकर रुक गई। कार चला रहे युवक ने बाहर निकलकर राणाजी एक्स्लेव की तरफ दौड़ लगा दी। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। उसकी पहचान सन्नी के रूप में हुई।



नई दिल्ली। जन औषधि के साथ स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश फैलाने के लिए देश भर में 25 स्थानों पर किया हेरिटेज वॉक का आयोजन।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में मंत्रों के बीच 418 जोड़ों का हुआ विवाह

दिव्य भारत संवाददाता

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एटीएल ग्राउण्ड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। जिसमें 418 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ भव्य रूप से किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 412 हिन्दू जोड़े एवं 6 मुस्लिम जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। सभी शादियां अपने रीति रिवाज के अनुसार हुईं, हिंदू धर्म की शादी वेद मंत्रों के उच्चारण से वहीं मुस्लिम शादियां निकाह के माध्यम से संपन्न की गईं। इस दौरान प्रत्येक जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का प्रमाण पत्र व एक-एक फलदार वृक्ष भी दिया गया।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य, सांसद के प्रतिनिधि बी एल पटेल, राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि राय साहब, समाजसेवी रोशन लाल ऊमरवैश्य, पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रान्तिकारी सहित अन्य अतिथियों ने सम्मिलित होकर नव दांपत्य जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

इस अवसर पर विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हर वर्ग के जोड़े सम्मिलित हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी इस आयोजन का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी भेदभाव के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी जोड़ों को बधाई देते हुये समाज कल्याण विभाग द्वारा किये गये भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक

- 412 हिन्दू जोड़े एवं 6 मुस्लिम जोड़े हुए एक दूजे के लिए
- नव दांपत्य जोड़ों को विधायक, जिलाधिकारी, सीडीओ एवं अन्य अतिथियों ने दिया आशीर्वाद



विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों को परिणय सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। यह योजना गरीब, असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी सोच का आगे बढ़ाते हुये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से गरीब बेटियों को एक परिणय सूत्र में बांधने का कार्य किया जा रहा है। हमारे देश में पलियों को धर्मपत्नी कहा जाता है, पति और पत्नी ये दुनिया का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता होता है और एक दूसरे के लिये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत सभी जोड़ों को विवाह

पूरे विधि विधान के साथ सम्पन्न हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नव दांपत्य जोड़े एक नये चरण में प्रवेश कर रहे हैं, सभी जोड़े खुशहाली के साथ रहे। उन्होंने सभी नव दांपत्य जोड़ों को बधाई एवं शुभकामनायें दी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने आये हुये अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत एक जोड़े पर सरकार द्वारा 51000 रुपए की धनराशि खर्च की जाती है जिसमें 35 हजार रुपए लड़की के खोते में, 10 हजार रुपए की उपहार सामग्री व 6 हजार रुपए की धनराशि से विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।

एटीएल ग्राउण्ड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनातर्गत विकास खण्ड सदर के 15, सण्डवा चन्द्रिका के 21, मानधाता के 33, लक्ष्मणपुर के 43, लालगंज के 18, रामपुर संग्रामगढ़ के 26, सांगीपुर के 27, गौरा के 09, शिवगढ़ के 13, बाबा बेलखरनाथधाम के 20, पट्टी के 22, मंगरीरा के 41, आसपुर देवसरा के 15, कुण्डा के 20, बिहार के 26, बाबागंज के 17, कालाकंकर के 37 जोड़ों व समस्त नगर पंचायत के 15 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ शादी सम्पन्न करायी गयी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के उपरान्त सभी जोड़ों व उनके परिवार लोगों ने भोजन ग्रहण किया और अपने-अपने घरों से लिये प्रस्थान किये। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकान्त देवें, डीसी मनरेगा अश्वनी सोनकर, ईओ नगर पालिका परिषद बेल्ला राकेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण सम्मिलित हुये। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर मोहम्मद अनीस द्वारा किया गया।

पुनर्मिलन का संगम बना प्रयागराज महाकुम्भ, अपनों से मिलाए गये मेले में बिछड़े हुए 50 हजार से ज्यादा लोग

दिव्य भारत संवाददाता

प्रयागराज। महाकुम्भ 2025 अपने दिव्य ,भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप के साथ 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व उपस्थिति से ऐतिहासिक आयोजन बन गया। संगम के तट पर आयोजित प्रयागराज महाकुम्भ में 144 साल बाद बने पुण्य संयोग में देश दुनिया से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। इस जन सैलाब के कारण कई लोग कुछ पलों के लिए अपनों से बिछड़ गए, लेकिन योगी सरकार की दूरदर्शिता और बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए किए गए प्रयासों की मदद से महाकुम्भ के इस विराट मेले में कुल 54,357 लोगों को उनके परिवारों से मिलाने में सफलता मिली है। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। यही नहीं पुलिस द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और नेपाल से आए श्रद्धालुओं का उनके परिवारों से सफलतापूर्वक पुनर्मिलन कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

इस दिव्य आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने कई अनुरक्षणीय पहल की, जो उपयोगी साबित हुई। इस बार महाकुम्भ में खोए हुए लोगों को शीघ्रता से उनके परिवारों से मिलाने के लिए योगी सरकार ने डिजिटल खोया-पाया केंद्रों की स्थापना की। महाकुम्भ में इनसे 35 हजार से श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया गया। अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति पर्व (13, 14 और 15 जनवरी) को खोए हुए 598 श्रद्धालु, मौनी अमावस्या के दौरान (28, 29 और 30 जनवरी) 8725 लोगों और बसंत पंचमी (2, 3 और 4 फरवरी) को डिजिटल खोया-पाया केंद्र की मदद से 864 लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया गया।

इसके अलावा अन्य स्नान पर्वों और सामान्य दिनों में खोए हुए 24,896 लोगों का भी उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन कराया गया। इस तरह महाकुम्भ के समापन पर 35,083 लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर संपूर्ण महाकुम्भ क्षेत्र में 10 डिजिटल खोया-पाया केंद्र स्थापित किए गए। इनमें अगर अत्याधुनिक एआई आधारित चेहरा पहचान

प्रणाली, मशीन लर्निंग और बहुभाषीय समर्थन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का संगम देखने को मिला तो वहीं गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं के प्रयास में मानवता और सेवा का अद्भुत मेल देखने को मिला। इनमें सबसे पुराना भारत सेवा केंद्र एवं हैमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति भी शामिल हैं। भारत सेवा केंद्र के भूले भटकों के शिविर के संचालक उमेश चंद्र तिवारी के मुताबिक, महाकुम्भ के समापन तक शिविर ने 19,274 बिछड़े महिला और

- महाकुम्भ में रंग लाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल, डिजिटल खोया-पाया केंद्र ने 35 हजार से अधिक बिछड़ों का कराया पुनर्मिलन
- निजी संस्थाओं का भी मिला सहयोग, भूले भटके शिविरों ने 19 हजार से अधिक महिला, पुरुष और 18 बच्चों को अपनों से मिलाया
- महाकुम्भ के आखिरी दिन तक मिलाए गए बिछड़े हुए लोग, बिछड़ों की सतत ट्रैकिंग कर मिलन कराया गया सुनिश्चित



पुरुष को अपनों से मिलाया। इसके अलावा कुम्भ मेले में बिछड़ गए सभी 18 बच्चों को भी उनके परिजनों से मिलाया गया। शिविर के माध्यम से न सिर्फ खोए हुए लोगों को खोजा गया, बल्कि उनके घरों तक पहुंचाने में भी मदद की गई।

महाकुम्भ के आखिरी स्नान पर्व महा शिवरात्रि तक खोया पाया केंद्रों और भूले भटके शिविरों में मेले में बिछड़ गए लोगों को उनके अपनों से मिलाने की प्रक्रिया पूरी हो गई।

खोया पाया केंद्र विशेष रूप से कारगर रहे। उन्होंने न सिर्फ बिछड़े लोगों का परिजनों से मिलन कराया, बल्कि बिछड़े लोगों की ट्रैकिंग भी की और जब तक वो परिवार से मिल नहीं गए तब तक प्रक्रिया को रिपीट किया गया।

मुजफ्फरपुर धरकरी बिहार के कपलेश्वर साहनी की सास कृष्णा देवी को केंद्र ने आखिरी दिन परिजनों से मिलाया। इसी तरह रायपुर छत्तीसगढ़ के बूजलाल चौहान की पत्नी की जंगी देवी भी अपने घर पहुंच गईं। नेपाल के बांके जिला जगज्जनन धारू के खोने की शिकायत उनके बेटे मनोज धारू ने लिखाई थी, लेकिन मनोज धारू का मोबाइल बंद मिला। इसी तरह सप्तरी नेपाल के सीताराम शाह ने पत्नी बिंदी के खोजने की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन सीताराम शाह ने जो मोबाइल नंबर शिकायत में दर्ज कराया वह गलत निकला। खोया पाया केंद्र की इस पहल से हर कोई संतुष्ट नजर आया और परिजनों के मिलने पर सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताना नहीं भूले।

प्राकृतिक खेती के विकास की बुनियाद बनेंगे गोवंश

आलोक पाण्डेय/दिव्य भारत

लखनऊ। योगी सरकार की मंशा गोवंश को प्राकृतिक खेती का आधार बनाने की है। यही वजह है कि सरकार छुट्टा गोवंश के संरक्षण का हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही पशुपालक गोवंश का पालन करें इसके लिए उनको लगातार प्रोत्साहन दे रही है। हाल ही प्रस्तुत बजट में सरकार ने छुट्टा गोवंश के संरक्षण के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसी क्रम में सरकार ने अमृत धारा योजना भी लागू की है। इसके तहत दो से 10 गाय पालने पर सरकार 10 बैंकों के जरिए 10 लाख रुपए तक आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराएगी। योजना के तहत तीन लाख रुपए तक अनुदान के लिए किसी गारंटर की भी जरूरत नहीं होगी। दरअसल जन, जमीन और जल की सेहत योगी सरकार के लिए प्राथमिकता है। इसका प्रभावी हल है प्राकृतिक खेती। ऐसी खेती जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मुक्त हो। गोवंश इस खेती का आधार बन सकते हैं। उनके गोबर और मूत्र को प्रसंस्कृत कर खाद और कीटनाशक के रूप में प्रयोग से ही ऐसा संभव है। इससे पशुपालकों को

- गोवंश के संरक्षण पर जोर दे रही योगी सरकार
- 10 गाय पालने पर 10 लाख रुपए तक आसान शर्तों पर मिलेगा ऋण
- योगी सरकार के प्रयास सुधरेगी जन, जल और जमीन की सेहत
- निर्यात बढ़ाने में भी मददगार होंगे प्राकृतिक कृषि उत्पाद

दोहरा लाभ होगा। खुद और परिवार की सेहत के लिए दुध तो मिलेगा ही जमीन की सेहत के लिए खाद और कीटनाशक भी मिलेगा। इनके उत्पादन से गौआश्रय भी क्रमशः स्वावलंबी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश, देश में प्राकृतिक खेती का हब बने। इसके लिए मुख्यमंत्री हर मुमकिन मंच से इसकी पुर्जो पेरवी करते हैं। वह किसानों को भारतीय कृषि की इस परंपरागत कृषि पद्धति को तकनीक से जोड़कर और समृद्ध करने की बात भी करते हैं। इसके लिए उनकी सरकार किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। गंगा के तटवर्ती गांवों और बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती पर सरकार का खासा जोर है। अब तो इसमें स्थानीय नदियों को भी शामिल कर

लिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद पूरी दुनिया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई है। हर जगह स्थानीय और ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से इनके दाम भी अच्छे मिलेंगे। फूड बिहेवियर में आया यह परिवर्तन वैश्विक है। लिहाजा इनकी मांग अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार का फोकस भी कृषि उत्पादों के निर्यात पर है। ऐसे में यह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक मौका भी हो सकता है। मालूम हो कि प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। सात वर्षों में यह बढ़कर दोगुना हो गया है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2017-2018 में उत्तर प्रदेश का निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये था। 2023-2024 में

यह बढ़कर 170 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने से अन्नदाता किसान खुशहाल होंगे। खास बात यह है कि प्राकृतिक खेती से जो भी सुधार होगा वह टिकाऊ (सस्टेनेबल), ठोस और स्थायी होगा। मुख्यमंत्री का गोवंश के प्रति प्रेम जगजाहिर है। वह अपने पहले कार्यकाल से ही गोवंश के संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। इस बाबत निराश्रित गोवंश के लिए गोआश्रय खोले गए। प्रति पशु के अनुसार भरण पोषण के लिए पैसा भी दिया जाता है। बजट के पहले अनुपूर्क बजट में भी इस बाबत 1001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री की मंशा इन गोआश्रयों को आत्मनिर्भर बनाने की है। ऐसा तभी संभव है जब इनके गोबर और मूत्र को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जाय। इसके लिए समय-समय पर सरकार स्किल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम चलाती है। साथ ही मनरेगा के तहत भी पशुपालकों को सस्ते में कैटल शेड, पशु बाड़ा और गोबर गैस लगाने की सहूलियत दी जा रही। मिनी नंदिनी योजना भी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है।

ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करेगी योगी सरकार

दिव्य भारत संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। इसके बाद प्रदेश की हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा संसाधन और डिजिटल युग के अनुरूप शैक्षिक प्रगति को सुनिश्चित करना है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय के साथ शिक्षा क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण छात्रों तक ई-बुक, डिजिटल कंटेंट और अन्य शैक्षिक संसाधनों की पहुंच आसान बनानी होगी। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने ग्राम

- प्रथम चरण में 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की होगी स्थापना
- ई बुक के साथ अन्य डिजिटल कंटेंट भी बच्चों को कराया जाएगा उपलब्ध
- ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत लाइब्रेरी की करेंगे देखरेख
- योगी सरकार हर डिजिटल लाइब्रेरी पर खर्च करेगी 4 लाख रुपये

पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, जहां बच्चों को किताबें, प्रश्नोत्तरी, वीडियो, ऑडियो लेक्चर तथा अन्य डिजिटल संसाधनों उपलब्ध कराए जाएं। इससे बच्चों में सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। सीएम ने लाइब्रेरी के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने के निर्देश दिये। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की देखरेख ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा की जाएगी।

नई 'दुनिया' के कौशल के लिए तैयार हो रहे यूपी के युवा

आशीष पाण्डेय/दिव्य भारत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने बीते साढ़े आठ सालों में कई ठोस कदम उठाए हैं। अब टेक्निकल एजुकेशन को और मजबूत करने के लिए सरकार नए और महत्वाकांक्षी कदम उठाने जा रही है। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस, स्मार्ट क्लासरूम, लैबोरेटरीज के अपग्रेडेशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना तक शामिल है। इसके अलावा, विज्ञान पार्क, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना के जरिए युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की योजना है। प्रदेश में डिप्लोमा स्तर की 184 संस्थाएं संचालित हैं, जहां युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही 36 नए राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणवांछनी हैं। सरकार ने अब तक 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं और नवीन तकनीक से लैस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने की तैयारी कर रही है। स्मार्ट क्लासरूम और प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये, जबकि एआई शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के लिए 1 करोड़ रुपये योगी सरकार खर्च करेगी।

- योगी सरकार टेक्निकल एजुकेशन में करने जा रही कई नई पहल
- राजकीय पॉलिटेक्निक में होंगे सेंटर ऑफ एक्सिलेंस और स्मार्ट क्लास
- लैबोरेटरीज को किया जाएगा अपग्रेड, एआई के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की होगी स्थापना
- प्रदेश में विज्ञान पार्कों तथा नक्षत्रशालाओं की होगी स्थापना
- वाराणसी और आगरा में आकार लेगी साइंस सिटी

व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1,90,064 सीटों पर युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से 47 संस्थानों में महिलाओं के लिए विशेष शाखाएं और 12 स्वतंत्र महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। सरकार का मानना है कि तकनीकी कौशल ही आने वाले समय में देश और प्रदेश के विकास की रीढ़ बनेगा।

भाजपा के राज में देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई : प्रमोद तिवारी

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत

प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता सांसद प्रमोद तिवारी के एक दिवसीय पट्टी में आगमन पर काँग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ.नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में कोहड़ौर मदफरपुर मार्ग पर भव्य स्वागत किया गया। सांसद प्रमोद तिवारी ने श्रीमती पनाऊ देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, केवटली, दियावा, पट्टी पहुंचकर हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के उपरांत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पट्टी व प्रबन्धक राम लवट यादव की माता श्रीमती पनाऊ देवी की मूर्ति का भव्य अनावरण किया गया।

इस अवसर पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि जीवन में सब का स्थान है, लेकिन सबसे पवित्र और आत्मिक रिश्ता मां से होता है। बच्चों को इस रिश्ते को जरूर निभाना चाहिए क्योंकि जहां पिता आपको शिक्षा दिलाता है वहीं मां आपको पालन पोषण करती है। आज का युवा कितना इतिहास जानता है यह मैं नहीं जानता लेकिन सर्वाधिक शासन देश पर काँग्रेस ने किया। पट्टी में आजादी की लड़ाई में जो बलिदान और त्याग का दीपक जला वह सदा कायम रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पट्टी से ही अपने राजनीति की शुरुआत की थी। हम मजबूत



तभी होंगे जब भारत तिरंगे के नीचे चलेगा, धर्म और जाति से सरकारें बनती हैं लेकिन देश कमजोर होता है। भाजपा के राज में देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 87 पर पहुंचा है। हवाई अड्डे, सड़क, कारखाने जनता के पैसे से बने हैं। भाजपा उद्योगपतियों के हाथों देश की विरासत बेच रही है। अंत में उन्होंने कहा कि अकेला चलना आसान होता है लेकिन विरासत को संभाल कर चलना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह अंतिम सांस तक तिरंगे के साथ ही रहेंगे।

जिला अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार सरोज, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शुभम मिश्रा, आसपुर देवसरा ब्लाक अध्यक्ष विवेक पांडे, बेलखरनाथ ब्लॉक अध्यक्ष बृजेश पांडे, शिवगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष रामकुमार पटेल, नगर पंचायत रामगंज अध्यक्ष बृजेश यादव, रामरतन तिवारी, अब्दुल रहमान, अभय तिवारी, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, सूर्य प्रकाश शुक्ला, वीरेंद्र यादव, डॉ.मुस्ली धर, श्याम शंकर तिवारी, हरिप्रसाद उपाध्याय, वीरेंद्र यादव सहित तमाम स्थानीय लोग उपस्थिति रहे।